वर्ष 12 • अंक 241 • 16 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 27 नवंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

नेपाल ने स्वर्ण आयात शुल्क बढ़ाया

सुभाष चंद्रा ▶▶ पृष्ठ 16

ससम्मान कर्ज समस्या का समाधान

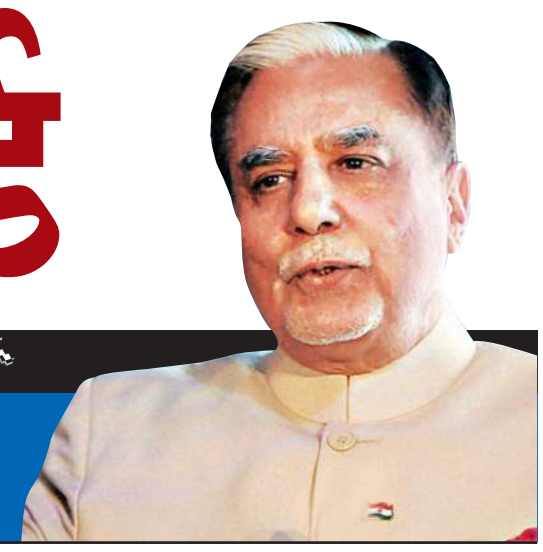

डॉलर रु. 71.50 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 78.70 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37802 ▼ 69 रुपये | सेंसेक्स 40821.30 ▼ 67.90 | निफ्टी 12037.70 ▼ 36.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12120.30 ▲ 82.60 | ब्रेंट क्रूड 63.40 डॉलर ▲ 0.30 डॉलर

एक नज़र

सीएसबी आईपीओ को 87 गुना आवेदन

सीएसबी बैंक के 410 करोड़ रुपये के आईपीओ को गुरुवार तक 87 गुना आवेदन प्राप्त हुए। निर्गम को सभी श्रेणी के निवेशकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। संस्थागत निवेशक श्रेणी में 62 गुना बोलियां मिलीं, वहीं धनाढ्य श्रेणी के निवेशकों की ओर से 164 गुना ओवदन प्राप्त हुए। खुदरा निवेशक श्रेणी में 43 गुना बोलियां मिलीं। निर्गम का मूल्य दायरा 193 से 195 रुपये रखा गया है। 195 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बैंक का बाजार पूंजीकरण 3,382 करोड़ रुपये होगा।

मुद्रा ऋण में बढ़ते एनपीए पर जताई चिंता

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने मंगलवार को बैंकों को सावधान करते हुए कहा कि उन्हें मुद्रा ऋण योजना पर नजर रखनी चाहिए। इस क्षेत्र में फंसी कर्ज राशि 3.21 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है इसलिए बैंकों को ऐसे कर्ज की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत की थी। मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 लाख रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। पृष्ठ 4

पैकेटबंद दुग्ध उत्पादों से जीएसटी हटे

खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पैकेटबंद दुग्ध उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद से इन पर जीएसटी हटाने के लिए पत्र लिखेगा। एफएसएसएआई केसीईओ पवन कुमार ने कहा कि हाल में खुदरा बाजार में इन उत्पादों की खुली बिक्री की गई थी, जिनकी जांच में गुणवत्ता एवं स्वच्छता स्थापित मानदंडों से कम पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दुग्ध उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अग्रवाल ने कहा कि एफएसएसएआई ने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को जांच उपकरण दिए हैं। प्राधिकरण ने देश के 25 लाख दूध वेंडरों में 1 लाख की जांच के लिए एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

सिटीग्रुप पर 4.39 करोड़ पाउंड का जुर्माना

बैंक ऑफ इंगलैंड ने सिटीग्रुप पर 4.39 करोड़ पाउंड का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। 2014 से 2018 के दौरान बैंकिंग समूह द्वारा निर्धारित नियामकीय रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने की वजह से ब्रिटेन के बैंकिंग नियामक ने इस पर जुर्माना लगाया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है। बैंक ऑफ इंगलैंड की पर्यवेक्षण इकाई प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा कि सिटीग्रुप ने रिपोर्टिंग डेटा प्रारूप को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया है।

आयकर विभाग के 21 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति

सरकार ने भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के पांचवें चरण में आयकर विभाग के 21 और अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के नियम 56 (जे) के तहत जनहित में बी समूह के 21 आयकर अधिकारियों को भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी।

शक्ति परीक्षण से पहले ही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिया इस्तीफा

उद्धव ठाकरे होंगे नए मुख्यमंत्री

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 26 नवंबर

महाराष्ट्र में शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले अजित पवार ने भी उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुबह उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए फडणवीस सरकार को बुधवार शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था।

देर शाम शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें ठाकरे को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया। इसके साथ ही गठबंधन सरकार में दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें ठाकरे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और तीनों दलों के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बालासहेब थोराट और राकांपा के जयंत पाटिल उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तीनों दलों के विधायकों ने मुंबई में देर शाम बैठक की। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। कोलंबकर ने कहा कि वह बुधवार को सदन का संचालन करेंगे। सदन सुबह 8 बजे शुरू होगा और इसमें विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।

ताजा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महाराष्ट्र और केंद्र के नेताओं की बड़ी राजनीतिक चूक मानी जा रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक खींचतान का पटाक्षेप होने से अब फिर से विपक्षी दल आर्थिक नरमी का मुद्दा उठाएंगे। इस मसले पर बुधवार को संसद में चर्चा हो सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में बुधवार को शाम 5 बजे तक सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। इसमें गुप्त मतदान नहीं कराने और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण कराने को कहा गया था। इसके बाद से ही भाजपा में घबराहट देखी जा रही थी। दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में 70वें संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का विपक्ष ने बहिष्कार किया।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र मामले में जो रवैया दिखाया है उससे तो यही लगता है कि मौजूदा सरकार के हाथ में संवैधानिक नियम सुरक्षित नहीं हैं। मनमोहन, गांधी और दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन में संविधान का कुछ हिस्सा पढ़ा।

इन गतिविधियों के बीच महाराष्ट्र के नव नियुक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपराह्न करीब 2 बजे इस्तीफा दे दिया। पवार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद भाजपा का उत्साह भी ठंडा पड़ गया और फडणवीस ने भी हालात भांप लिए। 23 नवंबर को सुबह आनन-फानन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने साढ़े तीन बजे एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर इस्तीफे की घोषणा कर डाली।

राज्य में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद से ही कांग्रेस इस पूरे मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रही थी।

- शिवाजी पार्क में 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ
- दो उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ
- भाजपा के कालिदास कोलंबकर बने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर
- अदालत ने बुधवार शाम 5 बजे तक फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था

30 नवंबर को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा वित्त आयोग

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 26 नवंबर

15वां वित्त आयोग 30 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में संभवत: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच कर बंटवारे से जुड़ी सिफारिश की जाएगी। जैसे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद आयोग को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कर संग्रह से रकम आवंटित करने के विषय पर विचार करना है।

हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर सरकार ने आयोग के साथ कोई संवाद नहीं किया है और न ही आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कुछ कहा है। माना जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले सरकार इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि शनिवार को आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप देगा। अधिकारी ने कहा, 'आयोग इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए कर बंटवारे पर सिफारिश करेगा ताकि बजट की तैयारियां शुरू हो सके।'

अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अधिकारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट तैयार करने में मदद मिलेगी। अंतरिम रिपोर्ट सौंपना कोई नई बात नहीं है क्योंकि इससे पहले तीन पूर्व वित्त आयोग भी ऐसी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रपति सरकार को रिपोर्ट अग्रसारित कर देंगे। वित्त मंत्रालय अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट संसद में पेश करेगा।' अधिकारी ने कहा कि 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व में आने के बाद मामला थोड़ा तकनीकी हो गया है। तकनीकी तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों को कर संग्रह से हिस्सा नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रदेशों का हिस्सा केंद्र के खाते से ही आता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि 15वां वित्त आयोग कर संग्रह से केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर को रकम आवंटित करेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो अधिनियम में जम्मू कश्मीर को राज्य के बराबर तरजीह देने की बात कही गई है। लद्दाख को किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही केंद्र के हिस्से से रकम मिलेगी।

एन के सिंह
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन

- संसद में पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय अंतरिम रिपोर्ट का करेगा अध्ययन
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है
- छह महीने बढ़ाया जा सकता है वित्त आयोग का कार्यकाल
- इस सप्ताहांत जारी हो सकती है अधिसूचना

ढाबों, रेस्तरां को टक्कर देने आएगी 7-इलेवन

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 26 नवंबर

किराना स्टोर के लिए मशहूर वैश्विक ब्रांड 7-इलेवन अगले साल फरवरी-मार्च तक मुंबई में अपना पहला स्टोर खोल देगी। लेकिन भारत में उसका यह पहला स्टोर दूसरे देशों में खुले किराना स्टोर की तरह नहीं होगा, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। यहां उसके स्टोर में लोगों को खाने-पीने की सुविधा मिलेगी। फ्यूचर रिटेल के साथ आ रही 7-इलेवन मुख्य रूप से दफ्तरों, कारोबारी परिसरों और कॉलेजों आदि के आसपास स्टोर खोलेगी, जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। इन स्टोर में किफायती दाम पर साफसुथरा खाना खिलाया जाएगा।

फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी किशोर बियाणी कहते हैं, 'मुंबई में अक्सर लोग सड़क किनारे बने ढाबों, ठेलों और रेस्तरां आदि में खाते-पीते दिख जाते हैं। हमें लगता है कि इस शहर में 7-इलेवन स्टोर के लिए बड़ी तादाद में ग्राहक मिल जाएंगे, जिन्हें हम संगठित तरीके से नाश्ता, भोजन और राता का खाना खिला सकते हैं। इन स्टोर पर ज्यादा रकम भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग चलते-फिरते खाना चाहते हैं, उनके लिए हम फल, जूस, स्नैक्स और कॉन्डिमेंट आदि भी रखेंगे।'

भारत पहला बाजार होगा, जहां 7-इलेवन किराना स्टोर के बजाय ढाबों और रेस्तरां से मुकाबला करेगी। माना जा रहा है कि पहले चरण में फ्यूचर समूह मुंबई में ही इसके स्टोर खोलेगा। सबसे पहले 5-7 स्टोर खोलने और उन पर करीबी नजर रखने की योजना है। बियाणी ने कहा कि इस कारोबारी ढांचे पर खास नजर रखनी होगी और एक साथ कई शहरों में इसे ले जाना कारगर नहीं होगा।

7-इलेवन जापान की कंपनी है, लेकिन इसका मुख्यालय अमेरिका में है। भारत कंपनी का 18वां बाजार होगा। दुनिया भर में इसके 67,000 से अधिक स्टोर है और इस कारोबार श्रेणी की यह सबसे बड़ी कंपनी है। यह खुद अपने स्टोर चलाती है या पेट्रोल पंपों, मॉल और शॉपिंग सेंटर के साथ हाथ मिलाकर वहां अपने स्टोर चलाती है।

जानकारों का कहना है कि भारत में 7-इलेवन जैसे ब्रांड पर जोर देश में बहु-ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर अंकुश लगाने की रणनीति से जुड़ा है। भारत खान-पान के खुदरा कारोबार में अनुमति आधार पर शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है, जिससे 7-इलेवन जैसे ब्रांड के लिए बिना किसी कठिनाई के कारोबार करना आसान हो जाता है।

- अगले साल फरवरी-मार्च तक मुंबई में खुलेगा पहला स्टोर
- स्टोर में खानपान की सुविधा होगी, छिटपुट किराना सामग्री भी होगी

एमेजॉन पर बढ़ेगी बिग बाजार की धमक

किराने की ऑनलाइन बिक्री की जंग में बिग बाजार हो या ग्रोफर्स या फ्लिपकार्ट, सभी अधिक से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिग बाजार को सबसे अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है। समझा जाता है किशोर बियाणी के नेतृत्व वाली हाइपरमार्केट श्रृंखला जल्द ही एमेजॉन इंडिया पर सबसे बड़ी किराना विक्रेता बनकर उभर सकती है। सूत्रों के अनुसार बिग बाजार फिलहाल एमेजॉन इंडिया के लिए प्रति स्टोर रोजाना 300 से 1,000 ऑर्डरों की आपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल के आरंभ तक इसमें चार गुना वृद्धि हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि एमेजॉन इंडिया दो घंटे में किराने की डिलिवरी के लिए देश भर में बिग बाजार के लॉजिस्टिक नेटवर्क और 2,000 से अधिक स्टोरों का व्यापक इस्तेमाल कर रही है। बिग बाजार फिलहाल एमेजॉन की प्राइम नाउ सेवा के लिए ऑर्डरों की भरपाई करती है और वह बेंगलूरु, दिल्ली एवं मुंबई के 18 स्टोरों से डिलिवरी करती है। परीक्षण के तौर पर पिछले कुछ समय से ऐसा किया जा रहा है। पृष्ठ 2

वाहनों की उम्र के आधार पर मूल्य ह्रास की सिफारिश

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के एक कार्य समूह ने मोटर वाहनों की बीमित राशि और आंशिक नुकसान के लिए वाहनों की उम्र के आधार पर मूल्य ह्रास का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद सभी विसंगतियां दूर करना और दावों का निपटाना आसान बनाना है। कार्य समूह ने कहा है कि निजी कारों के मामले में बीमित राशि की गणना विनिर्माता की मौजूदा तारीख के सूचीबद्ध वाहन मूल्य, जिनमें विनिर्माता द्वारा लगाई गई सभी एक्सेसरीज का मूल्य शामिल हो, के आधार पर की जा सकती है और उसकी आयु के आधार पर मूल्य ह्रास का समायोजन किया जा सकता है या इसकी गणना मौजूदा तारीख को वाहन के ऑन रोड मूल्य पर किया सकती है। पृष्ठ 4

दूरसंचार कारोबार: किसी को घाटा, किसी ने मोटा काटा

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 26 नवंबर

नॉर्वे की टेलीनॉर, रूस की सिस्तेमा और मलेशिया की मैक्सिस जैसी दूरसंचार कंपनियों को भारत में भारी घाटा उठाने के बाद देश से कारोबार समेट कर जाना पड़ा। वोडाफोन को भी शायद 680 करोड़ पाउंड से ज्यादा का निवेश बट्टे खाते में डालना पड़ सकता है और कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी निक रीड ने हाल ही में संकेत दिया था कि आइडिया सेल्युलर के साथ उनका संयुक्त उपक्रम बंद होने की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है।

मगर ऐसा भी नहीं है कि दूरसंचार के कारोबार में हर किसी को नुकसान ही उठाना पड़ा हो। कई कारोबारियों ने दूरसंचार क्षेत्र में अच्छा पैसा बनाया है। एस्सार के रुइया, पीरामल एंटरप्राइजेज के अजय पीरामल, मैक्स समूह के अनलजित सिंह, बीपीएल मोबाइल के संस्थापक राजीव चंद्रशेखर, हिंदुजा परिवार और एस्कॉर्ट्स के नंदा के साथ ही वोडाफोन इंडिया के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी असीम घोष ने दूरसंचार कारोबार से अच्छी कमाई की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियामक ने जब कई पेच डाल दिए तो विदेशी कंपनियों को मजबूरन भारतीय निवेशक तलाशने पड़े ताकि नियमों का अनुपालन किया जा सके। 2005 तक भारत में दूरसंचार क्षेत्र में 49 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति थी। तब विदेशी कंपनियों को भारतीय साझेदार की जरूरत पड़ती थी और कई बार कंपनी पर नियंत्रण के लिए एक से अधिक साझेदार बनाने पड़ते थे। मगर 2005 में नियमों में ढील दी गई और 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति दे दी गई, जिसे 2013 में बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया।

तमाम चुनौतियों और नियामकीय अनिश्चितताओं के बीच सभी कंपनियों ने भारतीय निवेशकों को सही समय पर अपना निवेश निकालने का मौका दिया। कुछ निवेशकों को अहसास हुआ कि दूरसंचार कारोबार में काफी पूंजी की जरूरत होती है और ग्राहक भी कम शुल्क देना चाहते हैं, जिससे रिटर्न हासिल करना काफी कठिन है। ऐसे में उन्हें देश में आने का प्रयास कर रही कंपनियों और तेजी से विस्तार की संभावना तलाश रही कंपनियों में खरीदार की झलक दिखी।

रुइया का हचीसन के साथ संयुक्त उपक्रम था, लेकिन हचीसन ने जब 2007 में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी वोडाफोन को 1,110 करोड़ डॉलर में बेच दी तो रुइया इसमें फंस गए और उन्होंने पुट ऑप्शन करार किया जिससे उन्हें बाद में हिस्सा बेचने का अधिकार मिल गया। 2008 में उन्होंने वोडाफोन-एस्सार में अपनी 33 फीसदी हिस्सेदारी ब्रिटेन की कंपनी को बेच दी। इस सौदे से उन्हें 500 करोड़ डॉलर मिले और 40 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त फायदा भी हो गया। रुइया समूह जब अपने कारोबार का विस्तार कर रहा था तो दूरसंचार कारोबार की बिक्री से मिली रकम से उसे काफी मदद मिली। समूह ने बाद में काफी कर्ज भी लिया और भारी कर्ज के कारण उसे 2-3 कंपनियां गंवानी भी पड़ीं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ साक्षात्कार में अनलजित सिंह ने दूरसंचार क्षेत्र में आने वाली कई भारतीय कंपनियों को लेकर संशय जताया था। सिंह ने कहा था कि उन्होंने मुंबई में परिचालन शुरू करने के बाद तीन सर्कलों के लिए बोली लगाई थी, लेकिन विजेता बोली उनकी बोली से चार गुना अधिक थी। उन्होंने कहा, 'मैंने भांप लिया कि यह कारोबार बड़े निवेशकों के लिए है।' सिंह ने 1998 में हचीसन के साथ अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इस सौदे से उन्हें 561 करोड़ रुपये मिले।

हचीसन-एस्सार देश भर में विस्तार की संभावना तलाश रही थी। इसी समय फाससेल के प्रवर्तक हिंदुजा ने हचीसन-एस्सार के साथ करार किया। (शेष पृष्ठ 2 पर)

किसने की कितनी कमाई

रुइया ने वोडाफोन-एस्सार में 540 करोड़ डॉलर में बेचा हिस्सा

अजय पीरामल ने 11 फीसदी हिस्सेदारी बेच 8,900 करोड़ रुपये बनाए

राजीव चंद्रशेखर ने बीपीएल में अपनी हिस्सेदारी एस्सार को 4,400 करोड़ रुपये में बेची

अनलजित सिंह ने तमाम सौदों से बनाए 2,300 करोड़ रुपये

हिंदुजा ने 45 करोड़ डॉलर में हचीसन-एस्सार को बेचा अपना हिस्सा

असीम घोष ने अपना हिस्सा करीब 600 करोड़ रुपये में बेचा

व्यापार गोष्ठी

सरकारी कंपनियों का विनिवेश कितना उचित?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या मुद्रा ऋण में एनपीए बढ़ने से बैंकों की बढ़ेगी मुश्किल

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या डीजीसीए के निर्देश से इंडिगो के परिचालन पर पड़ेगा असर?	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

खबरों में रहे स्टॉक

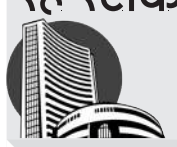

भारती एयरटेल

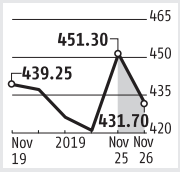

इक्रा ने अधिक प्रावधान का हवाला देते हुए घटाई दीर्घावधि रेटिंग

₹ 451.30 पिछला बंद भाव
₹ 431.70 आज का बंद भाव
▼ 4.34 %

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज

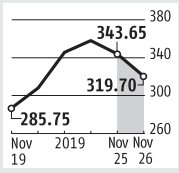

सुभाष चंद्रा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया

₹ 343.65 पिछला बंद भाव
₹ 319.70 आज का बंद भाव
▼ 6.97 %

इंडोको रेमेडीज

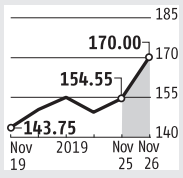

यूएसएफडीए ने हैदराबाद संयंत्र को दी हरी झंडी

₹ 154.55 पिछला बंद भाव
₹ 170.00 आज का बंद भाव
▲ 10.00 %

आईसीआईसीआई बैंक

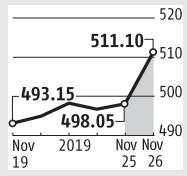

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 498.05 पिछला बंद भाव
₹ 511.10 आज का बंद भाव
▲ 2.62 %

डिश टीवी नेटवर्क

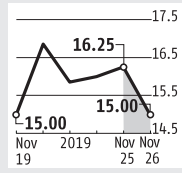

केयर ने लघु अवधि की रेटिंग घटाई

₹ 16.25 पिछला बंद भाव
₹ 15.00 आज का बंद भाव
▼ 7.69 %

संक्षेप में

टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी बने लक्ष्मीनारायणन

टाटा कम्युनिकेशंस ने ए. स्वामीनाथन लक्ष्मीनारायणन को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। इस पद से विनोद कुमार के जुलाई में इस्तीफे के बाद यह नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए की गई है, जो 26 नवंबर 2019 से प्रभावी होगी। *भाषा*

अरुण मिश्रा बने हिंदुस्तान जिंक के उप-सीईओ

वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अरुण मिश्रा को उप-मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। हिंदुस्तान जिंक ने बयान में कहा कि मिश्रा हिंदुस्तान जिंक की कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे और कंपनी की विस्तार परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाएंगे। *भाषा*

कोका कोला बेवरिजेस में नई नियुक्ति

रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरिजेस (एचसीसीबी) ने सबा शर्मा को मुख्य खरीद अधिकारी और प्रीति बलवानी को विधि सलाहकार (जनरल काउंसल) नियुक्त करने की घोषणा की है। *भाषा*

एमेजॉन से बढ़ेगी बिग बाजार की पैठ

फ्यूचर समूह की हाइपरमार्केट श्रृंखला एमेजॉन पर जल्द होगी सबसे बड़ा किराना विक्रेता

करण चौधरी और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 26 नवंबर

किराने की ऑनलाइन बिक्री की जंग में बिग बाजार हो या ग्रोफर्स अथवा फ्लिपकार्ट, सभी अधिक से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिग बाजार को सबसे अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है। समझा जाता है किशोर बियाणी के नेतृत्व वाली हाइपरमार्केट श्रृंखला जल्द ही एमेजॉन इंडिया पर सबसे बड़ी किराना विक्रेता बनकर उभर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, बिग बाजार फिलहाल एमेजॉन इंडिया के लिए प्रति स्टोर रोजाना 300 से 1,000 ऑर्डरों की आपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल के आरंभ तक इसमें चार गुना वृद्धि हो सकती है।

सूत्रों ने कहा कि एमेजॉन इंडिया दो घंटे में किराने की डिलिवरी के लिए देश भर में बिग बाजार के लॉजिस्टिक नेटवर्क और 2,000 से अधिक स्टोरों का व्यापक इस्तेमाल कर रही है। बिग बाजार फिलहाल एमेजॉन की प्राइम नाउ सेवा के लिए ऑर्डरों की भरपाई करती है और वह बेंगलुरु, दिल्ली एवं मुंबई के अपने 18 स्टोरों से डिलिवरी करती है। परीक्षण के तौर पर पिछले कुछ समय से ऐसा किया जा रहा है।

अगले चरण में इसे 12 शहरों तक बढ़ाया जाएगा और बाद में देश के उन 130 शहरों को इसके दायरे में लाया जाएगा जहां बिग बाजार के स्टोर मौजूद हैं। कंपनी के एक करीबी सूत्र ने बताया, 'प्राइम नाउ सेवाओं को एमेजॉन ऐप पर एकीकृत किया जा रहा है। ऐप पर प्राइम नाउ और बिग बाजार की इन्वेंटरी का पूरा एकीकरण अगले साल के आरंभ तक होने की उम्मीद है। बिग बाजार स्टोरों में प्राइम नाउ सेवा के तहत प्राप्त ऑर्डरों के लिए जगह और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जा रही है। इससे दो घंटे के भीतर डिलिवरी करने में मदद मिलेगी।'

एमेजॉन इंडिया ने अगस्त में चुनिंदा पिन कोड वाली जगहों के लिए एमेजॉन डॉट इन पर एमेजॉन फ्रेश स्टोर शुरू किया था। कंपनी अपनी घंटे में डिलिवरी सेवा के जरिये उपभोक्ताओं तक ताजा उत्पाद पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

बिग बाजार को एमेजॉन ऐप पर हर महीने करीब 32 करोड़ विजिटर हासिल होंगे और इससे उसे अपना ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमेजॉन ऐप के जरिये बिग बाजार के ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड को भी फायदा होगा जिसकी बिग बाजार के फूड कारोबार में करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी है। सूत्रों ने बताया कि एमेजॉन नाउ काफी संख्या में फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के ब्रांडों की डिलिवरी पहले से ही कर रही है। उसके प्रमुख ब्रांडों में टेस्टी ट्रीट, ड्रीमरी, वूम, कार्मिक, सांगीज किचन, गोल्डन हार्वेस्ट, कारा आदि शामिल हैं।

फिलहाल फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के सभी ब्रांड एमेजॉन नाउ पर सूचीबद्ध हैं। किशोर बियाणी के नेतृत्व वाली फ्यूचर रिटेल ने इसी साल अगस्त में बीएसई को दी जानकारी में कहा था कि एमेजॉन डॉट कॉम समूह की कंपनी फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है। इस सौदे के जरिये एमेजॉन की फ्यूचर रिटेल में 3.6 फीसदी प्रभावी हिस्सेदारी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार सौदे का आकार 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।

ऑनलाइन बाजार

- बिग बाजार फिलहाल एमेजॉन इंडिया के लिए प्रति स्टोर रोजाना 300 से 1,000 ऑर्डरों की आपूर्ति कर रही है
- फ्यूचर कंज्यूमर के ब्रांडों की बिक्री भी बढ़ेगी

गूगल पे प्लेटफॉर्म से राजस्व जुटाने पर नजर

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 26 नवंबर

देश में अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और वार्षिक लेनदेन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देते हुए गूगल की नजर अपने भुगतान प्लेटफॉर्म गूगल पे की सेवाओं को भुनाने पर है। गूगल पे के जरिये पर्सनल लोन संबंधी सेवाओं और सोने में निवेश के लिए लेनदेन पर कंपनी पहले से ही शुल्क वसूल रही है। इसके अलावा उसने यात्रा एवं रीचार्ज सेवाओं के लिए भी राजस्व मॉडल का अपनाया है।

गूगल पे के निदेशक (उत्पाद प्रबंधन) शरत बुलुसू ने कहा, 'रीचार्ज और यात्र के मामले में पहले से ही स्थापित वाणिज्यिक मॉडल है लेकिन अभी हम ग्राहकों अथवा व्यापारियों से शुल्क नहीं वसूलते हैं। यह अन्य मानदंडों पर काम करता है। पर्सनल लोन एवं सोने में निवेश संबंधी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लगाया गया है।'

हालांकि बुलुसू ने यह नहीं बताया कि किन क्षेत्रों और सेवाओं से कंपनी राजस्व सृजित करना चाहती है। यह पूछे जाने पर कि क्या उसमें नई सेवाएं होंगी अथवा मौजूदा, तो उन्होंने कहा, 'वास्तव में अभी हम नहीं बता सकते कि उसमें नई सेवाएं शामिल होंगी अथवा मौजूदा। फिलहाल हम इस क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं।'

भारत के लिए निकट भविष्य की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर बुलुसू ने कहा कि कंपनी की नजर अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने पर रहेगी। इसके लिए वह वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत भी कर रही है ताकि टोकन भुगतान का दायरा बढ़ाया जा सके। टोकन भुगतान क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड आधारित होते हैं जहां प्रत्येक डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक जटिल अनोखा एल्गोरिद्म सृजित होता है। गूगल पे पर उस एल्गोरिद्म को टोकन कहा जाता है। इस प्रकार भुगतान के लिए उपयोगकर्ता को कार्ड का ब्यौरा भरने की जरूरत नहीं होती लेकिन ऐसा केवल टोकन के जरिये किया जा सकता है।

मार्च से सितंबर के दौरान गूगल पे ने अपने उपयोगकर्ताओं की संख्या में करीब 49 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर के दौरान उसके अनोखे यूजर की संख 6.7 करोड़ तक पहुंच गई जो मार्च 2019 में 4.5 करोड़ थी।

मैकलॉयड रसेल के लिए अदालत के बाहर समाधान की तैयारी

अभिषेक रक्षित और नम्रता आचार्य
कोलकाता, 26 नवंबर

मैकलॉयड रसेल के लेनदार अदालत के बाहर कोई समाधान योजना तैयार करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी क्रम में आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में लेनदारों ने तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एलएसआई फाइनैंशियल सर्विसेज को नियुक्त किया है। लेनदारों का कहना है कि वे उस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर आगे की राह निर्धारित करेंगे।

इस अध्ययन के तहत मुख्य तौर पर बागों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यदि दबावग्रस्त विलियमसन मैगोर ग्रुप (डब्ल्यूएमजी) के लेनदार उसके 1,700 करोड़ रुपये के ऋण को पुनर्गठित करने के लिए तैयार हुए तो मैकलॉयड की वर्तमान एवं संभावित एबिटा का आकलन किया जाएगा।

एलएसआई फाइनैंशियल के प्रबंध निदेशक राज्य वी कजारिया ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'पहले चरण का काम पूरा हो गया है और प्रारंभिक रिपोर्ट लेनदारों को सौंप दी गई है। उन्होंने एबिटा स्तर और संभावना के बारे में दिलचस्पी दिखाई है।' मैकलॉयड की संभावित एबिटा का आकलन करने के लिए सलाहकार फर्म बागों में कर्मियों की छंटनी जैसे लागत घटाने के उपायों पर गौर कर रही है। इसके आवा पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैकलॉयड द्वारा पौधारोपण का भी जायजा लिया जाएगा।

हालांकि कजारिया ने कंपनी के वर्तमान एबिटा स्तर के बारे में बताने से इनकार किया लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह उद्योग के औसत 8 से 10 फीसदी से भी कम है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात पर जोर एवं कुछ अन्य कारणों से उसमें सुधार हो सकता है। कजारिया ने कहा, 'ऋण को पुनर्गठित किए बिना एबिटा में सुधार लाना मैकलॉयड के लिए आसान नहीं होगा।'

वित्तीय दबाव से जूझ रही कंपनी अपनी बागों में नए सिरे से पौधारोपण पहले से ही कर रही है और इससे उसे प्रति हेक्टेयर प्रतिफल में सुधार होने की उम्मीद है। कर्मचारियों की छंटनी जैसे लागत घटाने के अन्य उपायों से मार्जिन में सुधार होगा।

सूत्रों ने कहा कि फिलहाल कुल उत्पादन करीब 5.8 करोड़ किलोग्राम है। मैकलॉयड करीब 22 फीसदी उत्पादन का निर्यात करती है जबकि लगभग इतनी ही मात्रा की बिक्री निजी तौर पर करती है। जबकि शेष उत्पादन की नीलामी की जाती है। सूत्रों ने कहा, 'कंपनी की रणनीति निर्यात बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की है जो कहीं अधिक आकर्षक दिख रहा है।'

एलएसआई केवल चाय बागानों और उत्पादन पर गौर करेगी क्योंकि प्रमुख परिचालन क्षेत्र और चाय पर्यटन जैसे आय के पूरक स्रोतों पर गौर नहीं किया गया है। इस मामले के एक करीबी सूत्र ने बताया कि एनसीएलटी के बाहर की समाधान योजना में चाय बागानों की बिक्री और ऋण पुनर्गठन दोनों मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि 800 करोड़ रुपये के ऋण को पुनर्गठित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर गौर किया जा रहा है। इसके तहत ऋण पुनर्भुगतान के लिए समय-सीमा में विस्तार देने और बागों की बिक्री की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं जिससे 200 से 400 करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं।

एलएसआई फिलहाल एसबीआई कैप की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और रिपोर्ट मिलते ही वह बैंकों को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। एसबीआई कैप को लेनदारों ने एलएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ऋण पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।

आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में लेनदारों ने एलएसआई फाइनैंशियल सर्विसेज को व्यवहार्यता अध्ययन के लिए नियुक्त किया

बेयरिंग की कीमत के लिए साठगांठ का आरोप

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 26 नवंबर

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच में पाया गया है कि टाटा स्टील की इकाइयों, स्वीडन की कंपनी एसकेएफ और जर्मनी की कंपनी शेफलर ने बेयरिंग का मूल्य निर्धारित करने के लिए साठगांठ की थी। रॉयटर्स ने भी यह रिपोर्ट देखी है और ऐसे में तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि उस रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस मामले की जांच 2017 में शुरू की थी। उस समय आरोप लगाया गया था वाहन क्षेत्र में कच्चे माल की ऊंची लागत को ग्राहकों के कंधों पर डालने के लिए 2009 से 2014 के बीच पांच कंपनियों ने साठगांठ कर बेयरिंग की कीमतें निर्धारित की थीं। यदि आरोप सही साबित हुआ तो प्रतिस्पर्धा आयोग इन कंपनियों पर साठगांठ के प्रत्येक साल के लिए मुनाफे की तिगुनी रकम अथवा 10 फीसदी राजस्व में से जो भी अधिक हो, जुर्माना लगा सकता है।

यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा नियामक 2004 से 2011 तक बेयरिंग कीमतों के लिए साठगांठ करने के लिए 2014 में एसकेएफ, शेफलर और कलपुर्जा बनाने वाली तीन जापानी कंपनियों पर 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना लगा चुका है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच इकाई ने 6 मई की तिथि वाली एक जांच रिपोर्ट में कहा है कि उसने कंपनी के ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ का विश्लेषण किया और पाया कि एसकेएफ इंडिया, शेफलर इंडिया, नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील की बेयरिंग इकाई ने मूल्य पर चर्चा एवं सहमति बनाते हुए प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया है।

एसकेएफ बॉल-बेयरिंग बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। उसने एक बयान में कहा है कि उसने जांच में मदद की है और उसने आरोपों का खंडन किया है। शेफलर ने इस बाबत टिप्पणी के लिए आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया। टाटा स्टील और सीके बिड़ला समूह की इकाई नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सीसीआई की कार्यवाही गोपनीय थी।

सीसीआई की जांच इकाई की 106 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी टिमकेन की इकाई एबीसी बेयरिंग्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एबीसी बेयरिंग्स ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

ओडिशा में डिस्कॉम लाइसेंस हासिल करेगी टाटा पावर

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली/मुंबई, 26 नवंबर

टाटा पावर मध्य ओडिशा क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस हासिल करने जा रही है जो मुंबई और दिल्ली के बाद उसका ऐसा तीसरा लाइसेंस होगा। सूत्रों ने कहा कि भुवनेश्वर, कटक, पारादीप और ढेंकानल सर्किल में बिजली की खुदरा आपूर्ति एवं वितरण के लिए जारी निविदा के लिए टाटा पावर की बोली को अंतिम रूप दिया गया है। यह बिजली वितरण के निजीकरण का सरकार का दूसरा प्रयास है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण फ्रैंचाइजी पहले से ही सफलतापूर्वक परिचालन में हैं।

राज्य सरकार ने तीन अन्य क्षेत्रों में निजी बिजली वितरण और ओडिशा की केंद्रीय बिजली आपूर्ति यूटिलिटी (सीईएसयू) के तहत 15 डिविजन को अलग-अलग वितरण फ्रैंचाइजी मॉडल के लिए बोली आमंत्रित की थी। ओडिशा में बिजली विभाग के चार वितरण क्षेत्र हैं इसके साथ ही ओडिशा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां विभिन्न मॉडल के तहत बिजली वितरण को पूरी तरह निजी कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि टाटा पावर की तकनीकी बोली को मंजूरी मिल गई है और अब उसकी वित्तीय बोली का आकलन किया जा रहा है। बोली प्रक्रिया का संचालन ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) कर रहा है।

दूरसंचार: किसी को चपत किसी ने की मोटी कमाई

पृष्ठ 1 का शेष...

फाससेल गुजरात में मोबाइल सेवाओं का परिचालन कर रही थी, जबकि हचीसन का इस सर्कल में परिचालन नहीं था। लेकिन 2005 में एफडीआई सीमा बढ़ने के बाद हचीसन ने संयुक्त उपक्रम में हिंदुजा की 5.11 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी 45 करोड़ डॉलर में खरीद ली।

बीपीएल मोबाइल के राजीव चंद्रशेखर को भी अपना निवेश निकालने का अवसर दिखा और उन्होंने एस्सार समूह को 67 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 100 करोड़ डॉलर कमा लिए। इस सौदे के बाद बीपीएल का हचीसन-एस्सार में विलय किया गया और कंपनी महाराष्ट्र-गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में भी सेवाएं देने लगी। हचीसन-एस्सार ने एस्कोटेल से भी लाइसेंस खरीद लिया। एस्कोटेल एस्कॉर्ट्स समूह का संयुक्त उपक्रम था। हालांकि यह सौदा कितने में हुआ, उसका खुलासा तो नहीं हुआ लेकिन माना जाता है कि एस्कॉर्ट्स को 150 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। वोडाफोन में पैसा लगाना हमेशा ही अच्छा निवेश रहा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। 2008 में जब ग्राहक आधार बढ़ना शुरू हुआ तो सरकार ने नए लाइसेंस के दरवाजे खोल दिए। 22 से ज्यादा कंपनियों को 122 नए लाइसेंस जारी किए गए और दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो गई। इसकी वजह से शुल्क दरों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा शुरू हुई, जिससे कंपनियों का बहीखाता गड़बड़ाने लगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने नए लाइसेंसों को अवैध करार दिया और उन्हें रद्द कर दिया। इससे कई कंपनियां बाहर हो गईं।

वोडाफोन में निवेश करने वालों को पछतावा नहीं हुआ। अनलजित सिंह 2006 में इस क्षेत्र में वापस आए और विभिन्न समूहों में 1,019 करोड़ रुपये निवेश कर 7.58 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की। इसके तीन साल बाद उन्होंने अपना एक हिस्सा 533 करोड़ रुपये में बेच दिया। 2011 में उन्होंने अपनी शेष 2.39 फीसदी हिस्सेदारी असीम घोष को बेच दी। 2014 में जब सिंह ने पूरी तरह से इस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बेची तो उन्होंने 1,241 करोड़ रुपये की कमाई की। अजय पीरामल ने भी काफी कम समय के लिए वोडाफोन में निवेश किया था। कंपनी को 74 फीसदी एफडीआई सीमा का अनुपालन करने के लिए भारतीय निवेशक की जरूरत थी। 2012 में पीरामल ने कंपनी में 5,864 करोड़ रुपये में 11 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। दो साल उसे 8,900 करोड़ रुपये में बेचकर 52 फीसदी का मुनाफा कमाया। असीम घोष ने भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 600 करोड़ रुपये की कमाई की।

वाहन क्षेत्र के विलय-अधिग्रहण सौदों में तेजी

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 26 नवंबर

वाहन उद्योग में पिछले 12 महीनों से जारी मंदी के बावजूद इस क्षेत्र में विलय-अधिग्रहण सौदों का आकार करीब 73 फीसदी बढ़कर 44.9 करोड़ डॉलर हो गया जो जनवरी से अक्टूबर 2019 के दौरान 26 करोड़ डॉलर रहा था। इन सौदों में घरेलू एवं सीमापार विलय-अधिग्रहण के अलावा आंतरिक पुनर्गठन भी शामिल हैं। विलय-अधिग्रहण सौदों में वृद्धि को मुख्य तौर पर 27.5 करोड़ डॉलर के महिंद्रा-फोर्ड सौदे से बल मिला।

ग्रांट थॉर्नटन के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बिक्री 2017 के बाद पहली बार 10 करोड़ डॉलर के स्तर को पार करते हुए 2019 में 14.1 करोड़ डॉलर को छू गई। पिछले साल यह आंकड़ा महज 4.6 करोड़ डॉलर रहा था और इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इसमें 200 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, सीमापार सौदों का आकार कैलेंडर वर्ष 2019 में करीब 85 फीसदी घटकर 3.3 करोड़ डॉलर रह गया। पिछले साल यह आंकड़ा 21.5 करोड़ डॉलर रहा था।

- मंदी के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान वाहन क्षेत्र में विलय-अधिग्रहण 73 फीसदी बढ़ा
- महिंद्रा-फोर्ड के 27.5 करोड़ डॉलर के सौदे से घरेलू बिक्री को रफ्तार
- घरेलू बिक्री 2017 के बाद पहली बार 10 करोड़ डॉलर को पार कर 14.1 करोड़ डॉलर के करीब

ग्रांट थॉर्टन इंडिया एलएलपी के निदेशक पंकज चोपड़ा ने कहा कि नवंबर में घरेलू सौदों के कुल मूल्य में 2018 के के मुकाबले 2019 में तीन गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि सौदों की संख्या लगभग स्थिर रही। इससे मूल्यांकन में सुधार और इस क्षेत्र में निवेश की अधिक क्षमता का पता चलता है।

दूसरी ओर, सीमापार सौदों में अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चितता दिख रही है क्योंकि वहां समान अवधि के दौरान सौदा मूल्य में 5 गुना गिरावट दर्ज की गई है।

विलय-अधिग्रहण के मोर्चे पर किसी एक सौदे की वजह से वाहन क्षेत्र के सौदा मूल्य में 42 फीसदी की वृद्धि से कुल मिलाकर धारणा में सुधार का संकेत मिलता है। इस दौरान महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और फोर्ड का विलय एवं आंतरिक पुनर्गठन सबसे बड़ा सौदा रहा जिसका आकार 27.5 करोड़ डॉलर था।

अमेरिका की प्रमुख वाहन कंपनी फोर्ड मोटर ने इस सौदे के तहत भारत में अपनी अधिकांश परिसंपत्तियों का हस्तांतरण महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के साथ एक संयुक्त उद्यम को करने के लिए सहमत हुई है। नई कंपनी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) की अधिकांश ऑटोमोटिव परिसंपत्तियों को खरीदेगी जिसमें दो वाहन विनिर्माण संयंत्र भी शामिल हैं। हालांकि गुजरात के साणंद में फोर्ड का इंजन बनाने वाला संयंत्र इस सौदे का हिस्सा नहीं है।

नई कंपनी में महिंद्रा समूह की 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी जबकि फोर्ड की हिस्सेदारी 49 फीसदी रहेगी।

अन्य प्रमुख सौदों में महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव द्वारा 12.5 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स का अधिग्रहण, मिंडा इंडस्ट्रीज एवं डेल्विस जीएमबीएच के बीच 2.30 करोड़ डॉलर का सौदा और 55.8 लाख डॉलर के सौदे के तहत ग्रीव्स कॉटन द्वारा एम्पीयर व्हीकल्स में हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल हैं।

जो शेयर घटे, विश्लेषक उनसे हटे

अग्रणी 500 शेयरों में से एक तिहाई शेयरों को विश्लेषकों ने अपने नजरिये से किया बाहर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 26 नवंबर

कारोबारी अनिश्चितता, भारी-भरकम कर्ज और कंपनी प्रशासन के मसलों का सामना कर रही फर्मों के शेयरों का कवरेज विश्लेषक छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, अग्रणी 500 कंपनियों में से एक तिहाई से ज्यादा ने उनके शेयरों को कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या में कमी देखी है। जिन फर्मों से सबसे ज्यादा विश्लेषक दूर हुए उनमें डिश टीवी, येस बैंक और जेएसडब्ल्यू एनर्जी शामिल है।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि विश्लेषक किसी शेयर का कवरेज तब छोड़ते हैं जब उन्हें कंपनी की किस्मत में नाटकीय बदलाव के कारण आय का अनुमान जाहिर करना मुश्किल हो जाता है।

एनबीएफसी, दूरसंचार और ज्यादा पूंजी वाले अन्य क्षेत्र की कंपनियों का उस सूची में वर्चस्व है जिनका कवरेज एक साल पहले की तुलना में कम विश्लेषक कर रहे हैं। नुकसान उठाने वाली कंपनियों की बढ़ती संख्या के साथ शेयरों का कवरेज छोड़ने वाले विश्लेषकों की संख्या बढ़ रही है। बीएसई-500 में शामिल कंपनियों में से 48 ने वित्त वर्ष 2018-19 में नुकसान दर्ज किया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, प्रदर्शन के मोर्चे पर बार-बार निराशा से विश्लेषक ऐसे शेयरों का कवरेज छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। अगर मिडकैप या स्मॉलकैप का आकर्षण घट जाता है या ऐसे शेयरों में संस्थागत बिकवाली होती है तो विश्लेषक उसकी जगह अन्य सुर्खियां बनाने वाले शेयरों पर कवरेज शुरू करने के बारे में सोचेंगे। कंपनी या समूह पर असर डालने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस के मसले से भी कवरेज में कमी आती है। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि विश्लेषकों से बातचीत करते रहने वाली ज्यादा पारदर्शिता और अच्छे कंपनी प्रशासन के मानकों वाली कंपनियों को ज्यादा विश्लेषक कवर करते हैं। इससे अक्सर ज्यादा संस्थागत निवेशकों की भागीदारी व बेहतर मूल्यांकन देखने को मिलता है।

विश्लेषक के कवरेज में गिरावट इसका संकेत भी है कि उस शेयर में खास तौर से संस्थागत निवेशकों की रुचि घट रही है।

स्वतंत्र विश्लेषक अंबरीश बालिगा ने कहा, अगर कोई विशिष्ट शेयर बेहतर नहीं कर रहा है और संस्थागत दिलचस्पी घट रही है तो उस शेयर के कवरेज का मतलब नहीं बनता। शोध को ब्रोकिंग आय का सहारा मिलना चाहिए। दिलचस्पी का अभाव आय में परिवर्तित नहीं होगा। कोई भी ऐसे शेयर का कवरेज महज प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहता।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा, नए क्षेत्रों मसलन जीवन बीमा और संपत्ति प्रबंधन में कवरेज बढ़ाने के लिए विश्लेषक कुछ क्षेत्र में कवरेज बंद कर रहे हैं और उनकी जगह नए क्षेत्र को तवज्जो दे रहे हैं।

पिछली कुछ तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में विश्लेषकों का कवरेज ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर विश्लेषक हालांकि कंपनी विशेष के घटनाक्रम को कवरेज में गिरावट की वजह बताते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इसकी तकनीकी वजह भी हो सकती है। उद्योग के एक प्रतिभागी ने कहा, किसी खास ब्रोकरेज की तरफ से किसी क्षेत्र का कवरेज छोड़ना और विलय की घटनाएं भी उस शेयर में विश्लेषकों के कवरेज में गिरावट की वजह हो सकती है।

विगत में कुछ यूरोपीय निवेश बैंक अपना इक्विटी डेस्क बंद कर चुके हैं। साथ ही कुछ छोटे व मध्यम आकार वाले देसी ब्रोकरेज ने लागत घटाने के लिए अपना परिचालन कम किया है।

वैसे शेयर जहां कवर करने वाले विश्लेषकों की घटी संख्या

कंपनी	शेयर कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या: एक साल पहले	अब
डिश टीवी इंडिया	25	14
येस बैंक	48	40
डीएचएफएल	12	4
सीजी पावर	11	3
वीए टेक वाबैग	20	12
जीएसके कंज्यूमर	24	16
जेएसडब्ल्यू एनर्जी	24	17
वोडाफोन आइडिया	28	21
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस	15	8
पावर ग्रिड	34	28

स्रोत : ब्लूमबर्ग
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

ओयो होटल्स का शुद्ध घाटा 2,385 करोड़ रुपये

एजेंसियां
नई दिल्ली, 26 नवंबर

होटल कंपनी ओयो होटल्स ऐंड होम्स को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में 2,384.69 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। ओयो होटल्स द्वारा कंपनी पंजीयक के पास जमा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इससे पूर्व वित्त वर्ष में कंपनी को 360.43 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी की परिचालन आय 2018-19 में बढ़कर 6,456.90 करोड़ रुपये रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 1,413.02 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी के अनुसार वित्तीय परिणाम का अभी ऑडिट नहीं हुआ है और इसे मूल्यांकनकर्ताओं ने तैयार किया है न कि ऑडिटरों ने। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ये आंकड़े मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित हैं। कंपनी ने कहा है कि मूल्यांकन के मानदंड मसलन शेयर कीमतें उचित बाजार कीमत पर आधारित होती हैं।

कंपनी के बयान में कहा गया है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये अंतिम अंकेक्षित वित्तीय आंकड़े नहीं हैं और अंकेक्षित आंकड़े कंपनी अपनी सालाना रिपोर्ट के साथ जारी करेगी और उसे कंपनी पंजीयक के पास भी जमा कराएगी। कंपनी ने कहा कि मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में कंपनी का परिचालन खर्च बढ़कर 6,131.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में 1,246.84 करोड़ रुपये रहा था। वर्ष के दौरान कर्मचारी को दिए जा रहे फायदे पर खर्च भी उछलकर 1,538.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। गुड़गांव की इस कंपनी का मूल्यांकन जून 2019 में 5.32 अरब डॉलर (36,658.34 करोड़ रुपये) आंका गया है।

{संक्षेप में

टीवीएस मोटर ने पहला बीएस-6 वाहन उतारा

टीवीएस मोटर ने टीवीएस अपाचे व आरटीआर 4वी सीरीज का पहला बीएस -6 वाहन उतार दिया है। नया बीएस-6 मॉडल मौजूदा के मुकाबले 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक महंगा होगा, जो उनके अलग-अलग संस्करण पर निर्भर होगा। कंपनी ने मंगलवार को टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी मोटरसाइकल उतार दिया। टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी की कीमत 1.24 लाख ररुपये और और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी की कीमत 1.03 लाख रुपये है। देश भर में कंपनी की डीलरशिप पर मंगलवार से इसकी बुकिंग शुरू हो गई। *बीएस*

टोयोटा-सुजूकी शेयर सौदे को सीसीआई की मंजूरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजूकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच अल्पांश हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी। एक बयान के अनुसार सौदे के तहत सुजूकी मोटर में टोयोटा मोटर 4.94 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। वहीं टोयोटा मोटर में सुजूकी करीब 0.24 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी। *भाषा*

एस्सेल की कंपनी में निवेश को बिड़ला एमएफ ने किया अलग

बीएस संवाददाता
मुंबई, 26 नवंबर

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड ने एस्सेल समूह की कंपनी आदिलिंक इन्फ्रा ऐंड मल्टीट्रेडिंग में किए गए निवेश के लिए अलग पोर्टफोलियो बना दिया है, जिसे आम तौर पर साइडपॉकेटिंग कहा जाता है। बिड़ला म्युचुअल फंड की तीन योजनाओं एबीएसएल मीडियम टर्म फंड, एबीएसएल क्रेडिट रिस्क फंड और एबीएसएल डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्र में 793 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसका भुगतान मार्च 2020 में होना है। निवेशकों को भुगतान में आदिलिंक की नाकामी के बाद साइड पॉकेट का सृजन हुआ है।

एबीएसएल एमएफ ने इन तीनों योजनाओं के निवेशकों के भेजे संदेश में कहा है, 25 नवंबर 2019 को अल्पांश निवेशकों को आदिलिंक की तरफ से भुगतान किया जाना था क्योंकि अल्पांश शेयरधारकों ने उन्हें मिले पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। हमें जानकारी मिली है कि कंपनी ने आज अल्पांश शेयरधारकों को पुनर्भुगतान नहीं किया। इसके बाद हमने आदिलिंक में हुए निवेश के लिए अलग पोर्टफोलियो बना दिया है।

तीनों योजनाओं के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्रों में योजनाओं की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का 3.7 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक निवेश किया गया था। फंड हाउस ने कहा कि सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की मूल रूप से अनुमानित समयसीमा में विस्तार के कारण आदिलिंक पुनर्भुगतान नहीं कर पाई। साइड पॉकेट के तहत फंसी परिसंपत्तियों को मुख्य पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है।

तीन योजनाओं के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्र में 793 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसका भुगतान मार्च 2020 में होना है

अगर वहां से रिकवरी होती है तो इस कदम से मौजूदा निवेशकों के हितों को संरक्षित रखने में मदद मिलती है।

एबीएसएल एमएफ को उम्मीद है कि वह आदिलिंक से अपना बकाया वसूल करने में सक्षम होगी।

फंड हाउस ने निवेशकों को भेजे संदेश में कहा है, कुछ ही संभावित निवेशक हैं जो सड़क परिसंपत्तियों का सक्रियता से आकलन कर रहे हैं। हम सड़क परिसंपत्तियों की पूरी पोर्टफोलियो के लिए बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और अभी यह प्रक्रिया अलग-अलग निवेशकों के साथ अलग-अलग चरणों में है। साख वाले थर्ड पार्ट वेंडर के जरिए किए गए अहम मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि जब पोर्टफोलियो के लिए मुद्रीकरण की प्रक्रिया कामयाबी के साथ पूरी हो जाएगी तो पूरा निवेश वापस लिया जा सकता है। हम जल्द से जल्द बकाया वसूलने के लिए सभी विकल्प तलाश रहे हैं।

आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी एमएफ को मिली रकम

एस्सेल समूह ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ और एचडीएफसी एमएफ को भुगतान कर दिया है। प्रवर्तक की तरफ से ज़ी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी पिछले हफ्ते बेचने के बाद यह भुगतान हुआ है। अब एस्सेल समूह में आईसीआईसीआई प्रू एमएफ का निवेश शून्य रह गया, वहीं एचडीएफसी एमएफ को अभी भी कुछ बकाया वसूलना है।

सूत्रों ने कहा कि एस्सेल को शेयर के बदले कर्ज देने वाले म्युचुअल फंड मोटे तौर पर अपना बकाया वापस पाने में कामयाब रहे हैं, वहीं समूह के बुनियादी ढांचा उद्यम में निवेश अभी भी फंसा हुआ है।

आईसीआईसीआई प्रू एमएफ के प्रवक्ता ने कहा, हमें मूलधन के साथ उस पर ब्याज भी मिल गया है। अब आईसीआईसीआई एमएफ की किसी योजना का ज़ी की कंपनियों की तरफ से जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं है। उधर, एचडीएफसी एमएफ ने निवेशकों से कहा है कि उसे एनसीडी और उस पर बने ब्याज के लिए भुगतान का एक हिस्सा 166.8 करोड़ रुपये मिला है।

पीसी ज्वैलर की फिक्स्ड डिपॉजिट की रेटिंग घटी

अभिजित लेले
मुंबई, 26 नवंबर

केयर रेटिंग्स ने पीसी ज्वैलर लिमिटेड (पीसीजे) की सावधि जमाओं की रेटिंग बीबी से घटाकर बी कर दी है। नकदी की स्थिति और कंपनी के वित्तीय लचीलेपन में गिरावट के कारण रेटिंग घटाई गई है। पिछले कुछ महीने में फंड और गैर-फंड आधारित सीमाओं के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। साथ ही बाजार पूंजीकरण में लगातार गिरावट आ रही है और कंपनी के नकद व बैंक शेष में भी कमी आ रही है।

इस रेटिंग में हालांकि कंपनी के अनुभवी प्रवर्तकों शक्तियों को समाहित करना जारी रखा गया है, जिनका रत्न व आभूषण उद्योग में परिचालन का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पीसीजे के नाम से यह स्थापित ब्रांड है। कंपनी की फंड व गैर-फंड आधारित सीमा का औसतन पूरा इस्तेमाल हुआ है। मई 2019 में समाप्त पिछले 12 महीने में इस्तेमाल का औसत 91.13 फीसदी रहा है। 30 सितंबर 2019 को कंपनी की इन्वेंट्री 5,310 करोड़ रुपये थी, जो 30 जून 2019 को 5,092 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2019 को 4,988.11 करोड़ रुपये थी। 30 सितंबर 2019 को इन्वेंट्री में इजाफे की वजह त्योहारी सीजन थी।

थापर को सूचना उपलब्ध कराए सीजी पावर : सेबी

एजेंसियां
नई दिल्ली, 26 नवंबर

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी से प्रभावित सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्युशंस से बर्खास्त चेयरमैन गौतम थापर और अन्य को धोखाधड़ी की जांच के तहत की गई ऑडिट से जुड़ी वह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जिसकी उन्होंने मांग की है। थापर और अन्य ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी मांगी हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 25 नवंबर को कंपनी से 4 दिसंबर तक उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है। नियामक ने सितंबर में थापर, सीजी पावर के मुख्य वित्त अधिकारी और दो अन्य निदेशकों के संदिग्ध सौदों में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर उन्हें पूंजी बाजार में लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने आदेश में कहा, यह निर्देश दिया जाता है कि जो सूचना कंपनी के पास उपलब्ध है और जिसके बारे में थापर और अन्य निदेशकों द्वारा अनुरोध किया गया है, उसे 4 दिसंबर या उससे पहले उपलब्ध कराया जाए। नियामक ने कंपनी से ई-मेल का ब्योरा भी देने को कहास जिसका जिक्र ऑडिटर रिपोर्ट में किया गया है। उसी ई-मेल के जरिए सीजी पावर में कथित वित्तीय अनियिमितताएं सामने आईं।

सेबी ने अपने आदेश में सीजी पावर की कंपनी सचिव शिखा कपाड़िया से कहा है कि 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। सीजी पावर ने अगस्त में कहा था कि उसके निदेशक मंडल द्वारा शुरू की गई जांच में संचालन और वित्तीय मामलों में बड़ी चूक पाई गई है। इसमें कंपनी की कुछ संपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त कर्ज की राशि को कंपनी के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के खाते में डालना शामिल है।

साथ ही यह भी पता चला कि पहले की कुछ देनदारियों और दिए गए उधार को कम करके दिखाया गया था। कुल कथित धोखाधड़ी 3,000 करोड़ रुपये की बताई गई है। चेयरमैन पद से बर्खास्त थापर ने ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज की मांग की थी।

इससे पहले, सेबी ने बीएसई को कंपनी के 2015-16 और उसके बाद के खातों का विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

होंडा के मानेसर कारखाने में उत्पादन बहाल

होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने मंगलवार को कहा कि उसके मानेसर संयंत्र में स्थायी श्रमिकों के साथ उत्पादन का काम फिर शुरू हो गया है। हालांकि नौकरी से निकाले गए ठेका श्रमिक अब भी संयंत्र के बाहर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी होंडा ने अपने इस संयंत्र में नवंबर के पहले हफ्ते में कामकाज बंद कर दिया था। 200 ठेका मजदूरों को काम से निकाले जाने को लेकर श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। इस कारखाने में 1,900 स्थायी और 2,500 ठेका श्रमिक हैं।

कंपनी में 5 नवंबर से हड़ताल की स्थिति चल रही थी। उस दिन कथित रूप से कंपनी के प्रबंधकों ने कुछ ठेका मजदूरों को प्रवेश नहीं करने दिया था। कंपनी ने एक बयान में कहा, कंपनी ने 22 नवंबर को मानेसर संयंत्र में उत्पादन फिर शुरू करने का निर्णय किया।

सभी स्थायी श्रमिकों को 25-28 नवंबर के बीच में चार चरणों में ड्यूटी पर आने के लिए कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रमिक संगठन ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि संयंत्र पर काम फिर शुरू करके वह गलत कर रही है। *भाषा*

ओला लंदन में ड्राइवरों को साथ जोड़ने लगी

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 26 नवंबर

दुनिया की अग्रणी टैक्सी सेवा-प्रदाता उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस निरस्त हो जाने के बाद भारतीय कैब फर्म ओला ने ब्रिटेन की राजधानी में लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसे अगले कुछ हफ्तों में लंदन में ओला की कैब सेवा शुरू होने का संकेत माना जा रहा है।

ओला ने मंगलवार को बयान में कहा कि लंदन में आवागमन सेवा मुहैया कराने के लिए लाइसेंसधारक ड्राइवर उसके ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस अभियान के जरिये लंदन के करीब 50,000 ड्राइवरों को ओला से जोड़ने की तैयारी है।

ओला ने ब्रिटेन में अपना परिचालन अगस्त 2018 में कार्डिफ शहर से शुरू किया था। उसके बाद सॉफ्टबैंक-समर्थित ओला ने ब्रिटेन के कई अन्य शहरों- बर्मिंघम, लिवरपुल, रीडिंग, ब्रिस्टल, बाथ, कॉवेंट्री और वारविक में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर दिया है। अब वह ब्रिटिश राजधानी में अपने कदम रखने की तैयारी में जुट गई है। ओला के अंतरराष्ट्रीय कारोबार प्रमुख साइमन स्मिथ ने कहा, 'आज हम लंदन के हजारों ड्राइवरों को ओला प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम आने वाले कुछ हफ्तों में इस शहर में अपना परिचालन शुरू करने वाले हैं। हमने लंदन के लिए एक सशक्त परिवहन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लंदन परिवहन विभाग के ऊंचे मानदंडों के अनुकूल हैं।'

ओला को इस साल की शुरुआत में लंदन में परिचालन शुरू करने का लाइसेंस मिला था। इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ब्रिटेन के 27 इलाकों में पहले से ही 70 लाख यात्री कर रहे हैं। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सख्त सुरक्षा मानदंडों पर खुद का खरा साबित किया है। ओला भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 250 से भी अधिक शहरों में कैब सेवाएं दे रही है। उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस कुछ दिन पहले ही निरस्त हुआ है। लंदन के परिवहन विभाग ने सुरक्षा मानकों पर बार-बार नाकाम रहने के बाद उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है।

प्रतिद्वंद्वी फर्म उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस निरस्त होने के बाद ओला हुई सक्रिय

मुद्रा ऋण में एनपीए पर डिप्टी गवर्नर ने चेताया

अनूप रॉय
मुंबई, 26 नवंबर

मुद्रा ऋण में बढ़ते खराब कर्ज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने चिंता जताई है। सिडबी की ओर से माइक्रोफाइनैंस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जैन ने कहा कि वित्तीय सेवाओं, बैंकों की बढ़ती गतिशीलता के साथ बैंकों को निश्चित रूप से कर्ज लेने वालों की क्षमता भी सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिससे नया आय वर्ग न सिर्फ पेश की गई सेवाओं को लेने में सक्षम हों, बल्कि जरूरत व चयन के मुताबिक उचित सेवाएं व उत्पाद की पेशकश की जा सके।

जैन ने कहा, 'मुद्रा एक उदाहरण है। इस पर ज्यादा जोर दिए जाने से न सिर्फ तमाम लाभार्थी गरीबी रेखा के बाहर आए हैं बल्कि कर्ज लेने वालों की गैर निष्पादित संपत्तियों का स्तर भी बढ़ रहा है।'

उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए बैंकों को मंजूरी के स्तर पर ही पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है और कर्ज की पूरी अवधि के दौरान ज्यादा नजदीकी से नजर रखने की जरूरत है।

यह पहला मौका नहीं है जब केंद्रीय बैंक के अधिकारी ने बैंकों के बढ़ते खराब कर्ज को लेकर चेतावनी दी है। सूत्रों का कहना है कि जुलाई में सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बंधक मुक्त कर्ज में बढ़ते खराब कर्ज को लेकर भी नाराजगी जताई थी।

मुद्रा में तीन श्रेणी कर्ज हैं। शिशु- जिसमें 50,000 रुपये तक कर्ज दिया जाता है। वहीं किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपये और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक कर्ज दिया जाता है।

सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष 19 के अंत तक रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक शिशु में एनपीए 12.39 प्रतिशत, किशोर में 10.19 प्रतिशत एनपीए था। बहरहाल मुद्रा योजना के तहत सार्वजनिक किया गया कुल खराब कर्ज बहुत कम है और यह 2-3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

दो केंद्रशासित प्रदेशों के विलय का विधेयक पेश

दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन तथा दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया। निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दादरा और नगर हवेली एवं दमन तथा दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीति के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करते हुए दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का एक संघ राज्य क्षेत्र में विलय करने का निश्चय किया गया और इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के लक्ष्य दक्षता बढ़ाकर और कागजी कार्यों में कमी लाकर दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। *भाषा*

'दुरुस्त की जाएं केंद्र की परियोजनाएं'

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 26 नवंबर

सरकार को केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में क्रांतिकारी बदलाव करने की जरूरत है। या तो उन्हें 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित बनाया जाए, या उन्हें संयुक्त अनुदान के साथ राज्यों को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही उनकी डिजाइन और उसे लागू करने के तरीके में बदलाव किया जाए, जिससे वे प्रभावी हो सकें।

पंद्रहवें वित्त आयोग की ओर से जुटाई गई रिपोर्टों के विभिन्न अध्ययनों में से एक में यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। यह अध्ययन विभिन्न थिंक टैंकों द्वारा किए गए हैं। इनमें कुल 26 रिपोर्ट हैं और यह देखना अभी बाकी है कि इनमें से कितनी सिफारिशें 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं।

इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) की दो रिपोर्टों में 14वें वित्त आयोग के आवंटन के बाद राज्यों में विकास पर किए गए खर्च पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि किस तरह से राज्यों ने धन व्यय किया है और केंद्र प्रायोजिक योजनाएं किस तरह आगे बढ़ी हैं।

जताई चिंता

- इक्रियर की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम की जाए
- 20 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, लेकिन व्यवहार में उनकी संख्या 10 गुना ज्यादा
- केंद्र की योजनां पूर्ण वित्तपोषित हों व आंशिक सहायता वाली योजनाएं राज्यों को दी जाएं

केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर रिपोर्ट में कहा गया है, 'केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को विकास में हस्तक्षेप के रूप में ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उन पर किया गया सार्वजनिक व्यय केंद्र व राज्य में ज्यादा प्रभावी हो। सीएसएस की गणना से पता चलता है कि इनकी संख्या को लेकर कोई साफ संकेत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार बजट में सिर्फ केंद्रीय योजनाओं पर आवंटन पेश करती है।' इसमें कहा गया है, 'ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय सिर्फ 28 सीएसएस चल रही हैं, लेकिन हकीकत में इनकी संख्या 10 गुना ज्यादा है। ऐसा इसलिए है कि इन 28 योजनाओं में तमाम उप योजनाएं हैं जो अपने आप में योजना हैं।'

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तपोषण केंद्र व राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। वहीं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं का पूरी तरह वित्तपोषण केंद्र सरकार करती है। दरअसल 30 सीएसएस हैं, जिनके लिए 2019-20 में 3.32 लाख करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है।

रिपोर्ट में उन्हें 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित बनाने और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के आधार पर उनकी प्राथमिकता तय करने या कुल व्यय का 13 प्रतिशत अनुदान देकर उन्हें राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही इनकी डिजाइन और लागू करने के तरीके में भी क्रांतिकारी फेरबदल की सिफारिश की गई है।

2015-16 से 2019-20 के बीच राज्यों द्वारा किए गए खर्च पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग आवंटन की इस अवधि के दौरान सभी राज्यों की हस्तांतरण से कुल प्राप्तियां 91 प्रतिशत बढ़ी हैं और अनुदान के माध्यम से प्राप्तियां 65 प्रतिशत बढ़ी हैं। 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को हस्तांतरण पहले के 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाए, जिसकी कुछ सिफारिशें मोदी सरकार ने स्वीकार कर ली थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में कुल मिलाकर 18 राज्यों को फायदा हुआ है। इनमें से 7 हिमालय क्षेत्र के और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। कुल हस्तांतरण के हिसाब से 10 राज्यों को नुकसान हुआ है, जिसमें 4 हिमालय और पूर्वोत्तर के राज्य हैं।'

अंतराष्ट्रीय मानकों पर बीमा नियम

सुब्रत पांडा
मुंबई, 26 नवंबर

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के एक कार्यसमूह ने मोटर वाहनों की बीमित राशि और आंशिक नुकसान के लिए वाहनों की आयु के आधार पर मूल्यह्रास का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद सभी विसंगतियां दूर करना और दावों के निपटान में वस्तुनिष्ठता लाना है।

कार्यसमूह ने कहा है कि निजी कारों के मामले में बीमित राशि की गणना विनिर्माता की मौजूदा तारीख के सूचीबद्ध वाहन मूल्य, जिनमें विनिर्माता द्वारा लगाई गई सभी एसेसरीज का मूल्य शामिल हो, के आधार पर की जा सकती है और उसका आयु के आधार पर मूल्यह्रास का समायोजन किया जा सकता है या इसकी गणना मौजूदा तारीख को वाहन के ऑन रोड मूल्य पर किया जा सकता है, जिसमें इनवाइस पर दाम, सड़क कर और पंजीकरण शुल्क और विनिर्माता द्वारा लगाई गई सभी एसेसरीज का दाम शामिल हो।

दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि नई कारों का 3 साल तक कोई मूल्यह्रास नहीं माना जाए। उसके बाद कार की बीमित राशि चौथे साल के लिए 40 प्रतिशत मूल्यह्रास के हिसाब से रखी जाए। इसी तरह 4 साल के बाद 5वें साल तक 50 प्रतिशत मूल्यह्रास और 5 साल के बाद 55 प्रतिशत मूल्यह्रास और 6 साल के बाद कार का मूल्यह्रास 60 प्रतिशत माना जाए।

मसौदा के मुख्य बिंदु

- आसान मानक आधारित उत्पाद उपलब्ध हो सकता है
- मानक नो क्लेम बोनस के ढांचे
- कार के मूल्यह्रास के प्रतिशत पर 7 साल की उम्र तक होगा काम
- हाल के शुल्क के आधार पर नए वाहनों की श्रेणी का प्रस्ताव
- नामित चालक नीति- जिन्हें वाहन चलाने का अधिकार होगा, उनका नाम पॉलिसी में होगा जबकि अभी जिसका वाहन है, उसका नाम होता है
- नया सीमित कवर- कुल नुकसान और देनदारी
- इनबिल्ट मेडिकल व्यय कवर 25,000 रुपये
- टेलीमैटिक्स, पे एज यू ड्राइव, पे हाऊ टु ड्राइव की अवधारणा तकनीक में बदलाव

वहीं 7 साल के बाद बीमित राशि बीमाकर्ता और बीमा कराने वाले की आपसी सहमति के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

दोपहिया वाहनों के मामले में बीमित राशि की गणना चालू तिथि को विनिर्माता के सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिसमें विनिर्माता द्वारा लगाई गई सभी एसेसरीज का मूल्य शामिल होगा और इसका समायोजन वाहन के उम्र के मुताबिक मूल्यह्रास के आधार पर किया जाएगा। छह महीने पुराने दोपहिया के सूचीबद्ध मूल्य की 95 प्रतिशत बीमित राशि होगी। जैसे जैसे वाहन पुराना होता जाएगा, वाहन की बीमित राशि कम होती जाएगी।

अन्य श्रेणी के वाहनों के मामले में बीमित राशि की गणना खरीद के समय वाहन के ऑनरोड मूल्य के आधार पर होगी, जिसमें इनवाइस मूल्य, सड़क कर और लगाई गई सभी एसेसरीज की लागत शामिल होगी। मूल्यह्रास के मुताबिक इसका समायोजन होगा।

आंशिक क्षति के दावों में उम्र के आधार पर मूल्यह्रास की सिफारिश की गई है। एक साल तक के पुराने वाहन पर मूल्यह्रास 10 प्रतिशत होगा और इसी के मुताबिक इसमें बढ़ोतरी होगी।

कार्यसमूह ने यह भी कहा है कि एक साल से कम अवधि के लिए मोटर के खुद की क्षति की पॉलिसी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में जारी की जा सकती है। साथ ही एकल खुद की क्षति कवर भी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जा सकता है, जहां दीर्घावधि देनदारी नीति अनिवार्य है।

अन्य सुझावों में समूह ने सिफारिश की है कि मोटर बीमा के लिए टेलीमैटिक्स अपनाया जाए। कार्यसमूह ने कहा है, 'टेलीमैटिक्स आंकड़ों का केंद्रीय भंडार बनाया जा सकता है, जहां विभिन्न स्रोतों से आंकड़े आकर एक कॉमन पूल बनेगा। बीमा कंपनियों के भंडारण का काम करने वाला आईआईबीआई डेटा का प्रबंधन और उसका संरक्षण कर सकता है।'

बीमाकर्ताओं का मानना है कि नए मसौदा दिशानिर्देश वैश्विक मानकों के मुताबिक हैं और इससे बीमाकर्ताओं की निपटान गतिविधियां बेहतर होंगी।

बुनियादी ढांचे में 235 लाख करोड़ रु निवेश की जरूरत

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 26 नवंबर

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अगले एक दशक में 235 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा इस क्षेत्र में परियोजनाओं के हिसाब से अग्रणी हो सकते हैं क्योंकि यहां मांग ज्यादा है। क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी का मानना है कि अगले 10 साल में सड़क क्षेत्र में कुल निवेश का 50 प्रतिशत योगदान राज्यों का होगा।

निवेश का यह अनुमान केंद्र सरकार द्वारा इन वर्षों के दौरान 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अगले 5 साल में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश का वादा किया था।

चाहिए मोटी राशि

क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के वरिष्ठ निदेशक विवेक शर्मा ने कहा, 'इन राज्यों के अग्रणी होने की उम्मीद है क्योंकि उनका आधार कम है।'

एजेंसी ने राज्यों को 3 श्रेणी में डाला है। अग्रणी (इसमें गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र), मध्यवर्ती (इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा शामिल हैं) और ऊपर चढ़ने वाले (इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल)। राज्यों की इन श्रेणियों का उल्लेख करते हुए क्रिसिल ने इनके लिए विशेष रणनीति और कार्रवाई की सिफारिश की है, जिससे निवेश को गति मिल सके। हालांकि ऊपर चढ़ने वाले जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में बहुत खर्च किया है, वे कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह से सुस्त हो सकते हैं।

क्रिसिल ने आज कहा कि अगर भारत को भारी भरकम बुनियादी ढांचा तैयार करने का लक्ष्य हासिल करना है तो राज्यों को बुनियादी ढांचा पर खर्च अगले एक दशक (2021-30) में बढ़ाकर 110 लाख करोड़ रुपये या मौजूदा दशक के लिए अनुमानित 32 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा खर्च करना होगा।

क्रिसिल ने कहा है कि अगले 10 साल में देश के बुनियादी ढांचे पर 235 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत है और यह लक्ष्य हासिल करने के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत होने व बुनियादी ढांचे पर खर्च 6 प्रतिशत से ज्यादा करने की जरूरत होगी।

क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के अध्यक्ष समीर भाटिया ने कहा, 'बुनियादी ढांचे पर निवेश में अगर राज्य 50 प्रतिशत हिस्सेदारी करते हैं तो इस क्षेत्र को गति मिल सकती है। हाल के वर्षों में निजीक्षेत्र से निवेश कम हुआ है।'

अगले साल जून तक बनेगा कचरा निपटान संयंत्र!

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 26 नवंबर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सख्त रुख के बाद अब दिल्ली में औद्योगिक हानिकारक कचरे के निपटान के लिए संयंत्र बनाने का काम अब तेजी पकड़ सकता है। अगले साल जून महीने तक यह संयंत्र बनकर तैयार होने की संभावना है। जिससे खासकर नरेला-बवाना औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

उद्यमियों के मुताबिक इस समय अपशिष्ट निपटान के लिए जगह न होने के कारण औद्योगिक अपशिष्ट खुले में या यमुना नदी में बहाना उनकी मजबूरी है। जिससे उन्हें प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है।दिल्ली के बवाना में हानिकारक कचरे के लिए ट्रीटमेंट स्टोरेज ऐंड डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) स्थापित करने के तहत यह संयंत्र कई सालों से प्रस्तावित है। इस संयंत्र के लिए करीब 14 एकड़ जगह भी मिल चुकी है। पिछले साल जून में दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस संयंत्र को अपनी मंजूरी भी दी थी, लेकिन संयंत्र का काम रफ्तार नहीं पकड़ सका।

बीएस सूडोकू 3597

1	9						6	
8			1		3			
				5			9	
			4	7			2	9
		9				4		
4	5			6	8			
	3			2				
			5		1			7
	8						4	5

परिणाम संख्या 3596

5	4	1	2	7	3	8	6	9
6	7	9	5	8	1	4	2	3
2	8	3	4	6	9	5	7	1
7	1	8	3	9	6	2	4	5
4	3	2	7	5	8	9	1	6
9	6	5	1	4	2	3	8	7
8	9	4	6	1	5	7	3	2
3	5	6	8	2	7	1	9	4
1	2	7	9	3	4	6	5	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2125/2130, जौ 1825/1830, चावल मसूरी 2300/2350, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4200/4225, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1530/1600,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2145/2150, गेहूं शरबती 2750/2850, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2950,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1420, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1450, डीएमओ 1010, टरपीन लैस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1000/1030, खुरपा 920/940,चाकू 900/1030, रसकट 825/840, शक्कर 1050/1080, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3410, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3370, शामली 3320,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 900/920, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4225, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2600/2700, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5800, गेहूं (मिल) 2180/2185, मक्की 2070/2075, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4490/4500,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3900/3925, जौ 2050/2075,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4200/4250, ग्वारगम 7800/7900, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1900/1920, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6000/6200,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)124, राइसब्रान (अखाद्य) 121, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8100, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7800/8500, उड़द धोया 10000/11000, छिलका 10500/12300, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6150/6250, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4200/4300,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3900/3930, हरियाणा 3890/3920, राजस्थान 3850/3950, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2500/2600, सरसों खल 2170/2175,

फाजिल्का
गेहूं 2160/2170, सरसों 4225/4275 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/3925,कपास देशी 4850/4900, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5100, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2900/3000,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2160/2170, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2125/2130, बिहार 2250/2300, दाल उड़द छिलका 9700/10700, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5350/5450, काबली चना 5200/6000, राजमां चित्रा पुणे 7500/8800, शर्मिली 5500/6000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2165/2175, बासमती चावल 6400/6600, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2600/2700, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5200, स्टीम 6200/6300,

हिसार
ग्वार 3950/4000, सरसों 4050/4100, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1100, मैदा 1175/1200, देशी घी (एक ली/जार) 325/460, रिफाइंड (टीन) 1375/1390,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4000/4050, खल बिनौला मोटी 2450/2600, बिनौला 2700/3100, सरसों तेल 8550/8600, गेहूं 2125/2175, ग्वार 3900/3950, जौ 1825/1850, नरमा 5050/5100, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 241

शुरू हो सामान्य कामकाज

कई दिन चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (शामिल) नहीं होगी। हालांकि जो कुछ घटा वह किसी भी लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय तो नहीं हो सकता। यदि तीन अलग विचारधारा वाले दलों का साथ आना जनादेश का अपमान था तो भाजपा और अजित पवार ने रात के अंधेरे में जो कुछ किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा का मखौल उड़ाना था। अब जबकि इसका अंत होता दिख रहा है, बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सरकार चलेगी? या वह अपने ही विरोधाभासों और छोटी आंतरिक लड़ाइयों की शिकार हो जाएगी?

अतीत में शिवसेना ने कभी यह नहीं छिपाया कि वह स्वयं को विपक्षी दल मानती है, चाहे सत्ता में रहे या न रहे। वह प्रदेश का इकलौता दल है जिसने कोंकण तट पर जैतापुर परमाणु रिएक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था क्योंकि इससे मत्स्यपालन को खतरा था। यह ऐसी परियोजना थी जिसे कांग्रेस ने 2008 में भारी राजनीतिक कीमत चुकाकर हासिल किया था। भाजपा सरकार भी निरंतर अपने साझेदार दल के विरोध के साये में काम करती रही।

फ्रांस ने इस परियोजना में काफी निवेश किया है और अब वह इसके लिए सॉवरिन गारंटी चाहता है। अब तो आशंका यह है कि वह यहां और पैसा फंसाने के बजाय वापस भी जा सकता है। कांग्रेस ने परियोजना की शुरुआत के भी पहले घोषणा की थी कि वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच उच्चगति वाली रेल सेवा के खिलाफ है क्योंकि यह रेल मार्ग आदिवासी वन क्षेत्र से गुजरता है और स्थानीय लोगों को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस रेल मार्ग का विकास करने वाला जापान सांसे थामे प्रतीक्षा कर रहा है कि आखिर क्या होगा क्योंकि कांग्रेस सरकार का हिस्सा होने जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दोनों ध्रुवों के बीच फंसी है। उसके पास शिवसेना से केवल दो विधायक कम हैं लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा।

देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की नई सरकार गठन के बाद क्या वैसा ही कुछ करेगी जैसा कि अन्य दल विपक्ष से सत्ता में आने के बाद करते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने शुरुआती छह महीनों में हर उस चीज को नष्ट करने का काम किया जो उनके पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई थी।

यही बात राजस्थान पर लागू होती है जहां कांग्रेस की सरकार ने पिछली सरकार के कई निर्णय बदल दिए। इनमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात भी शामिल थी। नई सरकार को तमिलनाडु से सबक लेना चाहिए जो देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में शामिल रहा? कारण नीतियों में निरंतरता। एम करुणानिधि और जे जयललिता राजनीतिक रूप से धुर विरोधी थे लेकिन यदि उन्हें लगता कि कोई नीति सही है तो वे उसे जारी रखते और प्रायः कमी होने में उसमें सुधार करते। मध्याह्न भोजन योजना इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र के मतदाता, जो पिछले कुछ दिनों से सबसे अधिक परेशान थे, उनकी अपेक्षा है कि सरकार काम पर लग जाए।

सन 2015 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तलेगांव के निकट आने वाला फॉक्सकॉन का 500 करोड़ डॉलर का निवेश, पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा करने वाले मूल्यवर्धित कर में कटौती और लेनदेन की लागत में उल्लेखनीय कमी आदि जरूरी कदम हैं। नई सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि भाजपा को भले ही राज्य में अच्छी खासी क्षति पहुंची हो लेकिन वह अपनी ओर से कामकाज प्रभावित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी।

अजय मोहंती

फसल अवशेष जलाने की समस्या का निदान

फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने तथा पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान की खेती के प्रति हतोत्साहित करना होगा। बता रहे हैं **रमेश चंद**

कई वर्षों से दिल्ली तथा पश्चिमोत्तर भारत के अनेक हिस्सों में अक्टूबर और नवंबर में भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई कारक हैं लेकिन प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के लिए पड़ोसी राज्यों में धान की फसल के अवशेष जलाए जाने को वजह बताया जाता है। इस समस्या का स्थायी हल तलाशने के लिए हमें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जो किसानों को ऐसा करने से रोक सकें।

पारंपरिक तौर पर फसल अवशेष का इस्तेमाल पालतू पशुओं के चारे या घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता था। इसके एक हिस्से से कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी। समय के साथ फसल अवशेष की आपूर्ति बढ़ती गई और ईंधन तथा चारे के नए विकल्प आने से इसकी मांग कम होती गई। सूखे चारे की जगह हरे चारे ने ले ली और ईंधन में एलपीजी तथा अन्य स्रोत आ गए। इस क्षेत्र में एक दिक्कत यह भी है कि गैर बासमती धान के सूखे डंठल, गेहूं के डंठल की तुलना में बेहद खराब चारा माने जाते हैं। किसानों के पास इस अवशेष को जलाने या धरती में निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि देश भर में यह समस्या आम हो चली है। दिल्ली और उसके आसपास यह ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां हवा की गुणवत्ता पहले से खराब है।

पंजाब और हरियाणा के किसानों का गेहूं के फसल अवशेष जलाना आम है। लेकिन उसका नुकसान इतना अधिक महसूस नहीं होता है क्योंकि गर्मियों के दिन में तेज हवाएं धुएं को जल्दी ही फैला देती हैं। परंतु एक एकड़ भूभाग की गेहूं उपज के अवशेष जलाने का भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान होता है जितना कि एक एकड़ धान से। दुख की बात है कि इस तरफ बढ़ते रुझान को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे।

धान की खेती की बात करें तो अभी कुछ वर्ष पहले तक इसमें हार्वेस्टर का प्रयोग कम होता था और अधिकांश खेती हाथ से होती थी। हाथ से की जाने वाली खेती में धान की कटाई सतह से 6 से 10 सेमी ऊपर से होती थी। इससे अवशेष बहुत कम बचता और जुताई के बाद आसानी से निकल जाता। इसे एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाता जहां यह समय के साथ अपघटित हो जाता।

अब पंजाब में 94 फीसदी इलाके में हार्वेस्टर से खेती होती है। मशीन केवल ऊपर से 20 सेमी फसल काटती है और बाकी पौधा जस का तस छोड़ देती है। बचा हुआ अवशेष अगली फसल की तैयारी में मुश्किल पैदा करता है। धान कटाई के चार से छह सप्ताह बाद गेहूं की बुआई होती है। ऐसे में खेत को जल्दी साफ करना एक समस्या होती है। अधिकांश किसान आग लगाने का विकल्प चुनते हैं जो जल्दी भी होता है और इसकी लागत भी कुछ नहीं होती। परंतु यह पर्यावरण के लिए घातक है। पंजाब में जहां 75 फीसदी खरीफ रकबा धान है और इसका भी 78 फीसदी हिस्सा जलाया जाता है, वहां यह समस्या ज्यादा गंभीर है।

कुछ किसानों को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है और वे इस अवशेष को मिट्टी में दबाते हैं। इसके लिए इस अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होता है ताकि उनको जुताई के दौरान मिट्टी में मिलाया जा सके। इससे उर्वरता बढ़ती है और अवशेष का अपघटन हो जाता है। यह अपघटन बहुत धीमी गति से ही सही लेकिन वातावरण में मीथेन उत्सर्जित करता है। इसमें किसान को पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इसमें कई मशीन प्रयोग की जाती हैं और इसकी लागत करीब 3,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। इसका बड़ा हिस्सा अगली फसल की लागत में जुड़ जाता है।

केंद्र सरकार ने संबंधित मशीनरी की खरीद पर भारी सब्सिडी की व्यवस्था की है ताकि फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाया जा सके। बहरहाल, लागत के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा। इसके अलावा सब्सिडी भी चुनिंदा कंपनियों के उपकरणों पर है।

आवश्यकता इस बात की है कि देश के इस हिस्से में फसल अवशेष जलाने का दीर्घकालिक हल निकाला जाए। इससे निपटने के लिए तीन तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, फसल अवशेष से बायो-सीएनजी का उत्पादन। इस प्रक्रिया में उत्सर्जन भी न के बराबर होगा। बायोगैस निकालने के बार शेष बचा अवशेष खाद के काम आएगा। विशेषज्ञों से बातचीत से पता चलता है कि धान के डंठलों का सीएनजी के लिए इस्तेमाल किफायती है। इसकी प्रक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता। ऐसे निवेश के लिए रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पंजाब सरकार ने बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। पंजाब के संगरूर जिले में जर्मनी के निवेश से एक संयंत्र लगा है जबकि दूसरा हरियाणा के करनाल जिले में लग रहा है। केंद्र और राज्यों को बायो-सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए और संयंत्र लगाने के इच्छुक पक्षकारों को जल्द और रियायती ऋण देना चाहिए।

दूसरा विकल्प है बायोमास के परिवर्तित स्वरूप को ताप बिजली घरों में कोयले के स्थान पर प्रयोग करना या औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन के रूप में आजमाना। धान के प्रचुर उत्पादन वाले इलाकों में यह तरीका भी कारगर हो सकता है।

तीसरा विकल्प है बायोमास का शीघ्र अपघटन कर उसे जमीन में मिला देना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबायल फॉर्मूला बनाया है जो धान के बायोमास को 20-25 दिन में अपघटित कर देता है। अब वे इस तकनीक को खेतों में प्रयोग करने लायक बना रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह तकनीक जल्दी ही खेतों में प्रयोग के लिए तैयार होगी।

इन विकल्पों के सहारे कचरे को संपत्ति में बदला जा सकता है और इसके साथ ही यह धान के अवशेष जलाने से भी देश भर में छुटकारा दिला सकते हैं। बीते तीन दशक के दौरान हमारी खेती के तरीके में भी बदलाव आया है। इसके लिए कच्चे माल पर सब्सिडी और उत्पादन मूल्य नीति जिम्मेदार है। आज हम मांग से 10 फीसदी अधिक चावल उगा रहे हैं। जाहिर है ऐसा नीतियों के चावल उत्पादन के पक्ष में झुके होने से हो रहा है। इसका असर भूजल पर पड़ रहा है। इससे पर्यावरण खराब हो रहा है और राजकोषीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। हमें अपनी नीतियों में संशोधन कर पंजाब और हरियाणा को धान की खेती से विमुख करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना बंद करने और उस सब्सिडी को भिन्न स्वरूप में किसानों को देने से भी फर्क पड़ेगा।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

कर राजस्व में आनुपातिक बढ़त का कर बंटवारे पर असर

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

पिछले 28 वर्षों में 2002-2003 में देश में टैक्स बॉयंसी (सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मुकाबले कर राजस्व में आनुपातिक इजाफा) सर्वाधिक रही थी। उस वर्ष टैक्स बॉयंसी 2 दर्ज की गई थी। यानी केंद्र का सकल कर राजस्व महंगाई समायोजित किए बिना देश की आर्थिक वृद्धि दर या नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ा था। उस समय वित्त मंत्रालय की कमान यशवंत सिन्हा के पास थी।

टैक्स बॉयंसी देश की कर प्रणाली की कार्य क्षमता मापने का एक प्रमुख संकेतक है। इससे जीडीपी में आई तेजी की प्रतिक्रिया में कर संग्रह के स्तर का पता चलता है। टैक्स बॉयंसी मोटे तौर पर कर करदाताओं की संख्या, कर प्रशासन की कार्य कुशलता एवं उनके दोस्ताना रवैये और कर दरों की सरलता पर निर्भर करती है। हालांकि केवल एक वर्ष के टैक्स बॉयंसी के आधार पर कर प्रणाली की कार्य कुशलता एवं सक्षमता या आर्थिक वृद्धि के मुकाबले कर संग्रह के आंकड़े को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जा सकता है। कई ऐसे कारक हैं, जो टैक्स बॉयंसी को उछाल देते हैं या इसमें कमी लाते हैं। कराधान से जुड़ी नीतियां भी टैक्स बॉयंसी रेट को प्रभावित करती हैं और इनका आकलन एक लंबी अवधि के आंकड़ों एवं रुझान को देखकर ही किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए केवल एक वर्ष ही टैक्स बॉयंसी 2 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था और 2001-02 में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। उस वर्ष देश की नॉमिनल जीडीपी दर 8 प्रतिशत से कुछ अधिक रही थी। लिहाजा, कर बॉयंसी ऋणात्मक रही और देश में आर्थिक सुधारों की कसरत के बाद केवल एक बार यह इतने निचले स्तर पर रही थी। एक रुचिकर बात यह है कि सिन्हा के कार्यकाल में ही देश में सर्वाधिक और सबसे कम टैक्स बॉयंसी दर्ज हुई थी। वित्त मंत्री के तौर पर अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्हें दो वर्षों में कमतर टैक्स बॉयंसी से जूझना पड़ा, हालांकि शेष तीन वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी सराहनीय रही।

इस मापदंड के आधार पर सिन्हा का प्रदर्शन एक और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के मुकाबले थोड़ा ही कमतर माना जा सकता है। मनमोहन सरकार में चिदंबरम 2004-05 से 2008-09 तक देश के वित्त मंत्री थे। इस दौरान बतौर वित्त मंत्री उनके पहले चार वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी 1.3 से 1.7 के बीच रही। यह एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। पांचवें वर्ष यानी 2008-09 में (हालांकि मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद चिदंबरम ने दिसंबर 2008 में वित्त मंत्रालय छोड़ दिया था) टैक्स बॉयंसी में खासी कमी आई और यह कम होकर करीब 0.2 रह गई। टैक्स बॉयंसी में इतनी अधिक गिरावट के लिए वैश्विक वित्तीय संकट और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए गए आर्थिक प्रोत्साहन जिम्मेदार थे।

वैसे किसी वर्ष में टैक्स बॉयंसी पर उस दौरान घटित प्रतिकूल बातों का प्रभाव दिख सकता है, लेकिन अमूमन करीब पांच वर्षों की अवधि में दीर्घ अवधि के टैक्स बॉयंसी के रुझान कुछ वर्ष पूर्व नीतियों में हुए बदलाव के नतीजे होते हैं। नीतियों में बदलाव के परिणामस्वरूप टैक्स बॉयंसी पर कुछ समय बाद होने वाले असर की अनदेखी शायद ही की सकती है। लिहाजा वर्ष 1991-92 और 1997-98 के दौरान सात वर्षों में चार में टैक्स बॉयंसी औसतन 1.0 से 1.3 के बीच रही थी और शेष तीन वर्षों में यह कमजोर थी। हालांकि इन वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का असर बाद के दशक में स्पष्ट तौर पर दिखा। इस दौरान भी कुछ साल ऐसे रहे जब टैक्स बॉयंसी पर आर्थिक घटनाक्रम के कारण असर देखा गया।

सिन्हा ने कर सुधार, खासकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में, के जो उपाय किए थे उनसे चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान टैक्स बॉयंसी में मजबूती लाने में मदद मिली। सिन्हा के बाद चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। 2009-10 और 2011-12 की चार वर्षों की अवधि में जब प्रणव मुखर्जी दोबारा वित्त मंत्रालय लौटे तो टैक्स बॉयंसी कमजोर रही और दो वर्षों में यह 1 से कम रही और शेष दो अवधि में 1 से अधिक दर्ज की गई।

जब अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बने तो उनके पांच वर्षों के कार्यकाल में भी टैक्स बॉयंसी मजबूत रही। उनके कार्यकाल के पहले वर्ष टैक्स बॉयंसी 1 से नीचे जरूर रही, लेकिन तीन लगातार वर्षों में इसमें खासा सुधार हुआ और यह 1.0 से 1.6 के बीच रही। हालांकि अंतिम वर्ष यानी 2018-19 में यह कम होकर 0.7 रह गई। 2019-20 की पहली छमाही में जब केंद्र का सकल कर राजस्व 2018-19 की समान अवधि के मुकाबले महज 1.5 प्रतिशत दर से बढ़ा तो टैक्स बॉयंसी कम होकर करीब 0.15 रह गई। यह इस धारणा पर आधारित था कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर पहली छमाही में 10 प्रतिशत थी।

टैक्स बॉयंसी में आने वाली यह गिरावट केंद्र सरकार के खजाने के लिए चिंता का विषय है। इससे राजकोषीय मजबूती लाने की सरकार की योजना खटाई में पड़ सकती है और केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व साझा करने की 15वें वित्त आयोग की गणना का आधार कमजोर हो सकता है। अगर मौजूदा टैक्स बॉयंसी का इस्तेमाल अगले 15 वर्षों के दौरान राजस्व वृद्धि के आंकड़े दर्शाने के लिए होता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए राजस्व संबंधी चुनौतियां अधिक विकट हो सकती हैं। 15वें वित्त आयोग के लिए एक यक्ष प्रश्न यह है कि वह आने वाले वर्षों में टैक्स बॉयंसी की गणना के लिए अधिक विश्वसनीय आधार पर कैसे पहुंचेगा। अगर यह त्रुटिपूर्ण आकलन करता है तो कर संग्रह की बुनियाद बेजा साबित हो सकती है, जिससे कर बंटवारे की नई विधि पर प्रतिकूल असर होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच कर साझा करने के लिए आवश्यक सिफारिश करने से पहले 15वें वित्त आयोग को टैक्स बॉयंसी के विश्वसनीय रुझान का आकलन करना होगा।

कानाफूसी

मान-सम्मान और अपमान

लोकसभा चुनाव में भारी पराजय के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेता खुद को हाशिये पर महसूस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के प्रदेश कांग्रेस पर प्रभावी होने के बाद से उनका असंतोष कम होने के बजाय बढ़ा ही है। पार्टी के नए ढांचे को लेकर उन नेताओं के निरंतर टीका-टिप्पणी करते रहने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष सिंह और पूर्व विधायक सिराज मेहदी समेत प्रदेश के 10 बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया गया और बाद में उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। इन नेताओं का कहना है कि कुछ नेता पार्टी को निजी कंपनी की तरह चला रहे हैं और उनके मन में पुराने नेताओं के योगदान को लेकर रत्ती भर भी सम्मान का भाव नहीं है।

आप का दावा

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की अंदरूनी खींचतान के चलते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुना है। पुरी ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा यह चुनाव पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ेगी। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने कहा कि उनका अर्थ यह था कि पार्टी तिवारी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। भाजपा ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। आप का दावा है कि पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता और विजय गोयल भी तिवारी के साथ इस पद के दावेदार हैं।

हरदीप सिंह पुरी

आपका पक्ष

संविधान दिवस और भारतीय नागरिक

संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश ने संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार कर संवैधानिक दायरे में रहकर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया था। दुनिया के कई देशों को यह संदेह था कि क्या भारत में मौजूद अनेक धर्म, जाति, पंथ के चलते वह अपने संवैधानिक मूल्यों को टिका पाएगा। लेकिन आज देश अपना 70वां संविधान दिवस सफलता से मना रहा है जो इस संदेह को मिटा देता है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पूरी तरह प्रस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। देश में विविध सरकारी संस्थाओं, संगठन, स्कूल-कॉलेज द्वारा संविधान दिवस आयोजित कर उसमें मौजूद प्रमुख मूल्यों की बात भाषणों द्वारा रखी जाती है। लेकिन देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो संविधान में मौजूद बुनियादी तथ्यों से अपरिचित है, जबकि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह कम से कम संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य जैसे तत्त्वों से अच्छी तरह परिचित हो। यह बुनियादी बात व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था एवं मूल्य, सरकार की जिम्मेदारियां, नागरिक के अधिकार, देश के प्रति नागरिक के कर्तव्य आदि का बोध कराता है। अधिकतर स्कूलों में विज्ञान एवं गणित पढ़ाने में गंभीरता दिखाई जाती है लेकिन अक्सर सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रति उदासीन रवैया होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही महत्त्व देना जरूरी है क्योंकि यह विषय देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने में काफी मदद करता है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

संविधान दिवस के अवसर पर संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष

मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली

पिछले कुछ वर्षों में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने वाले ग्रामीणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे कई प्रकार के असंतुलन भी उत्पन्न हो रहे हैं। शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है। वहीं गांवों में कामगारों की कमी आने लगी है। इसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्हें अस्थायी या मौसमी पलायन करने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और इसका 62 प्रतिशत हिस्सा 59 वर्ष से कम आयु का है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग की है। इस तरह भारत विश्व का सबसे युवा देश है। अगर पलायन जीविका के परंपरागत स्रोत पर संकट आने के कारण हो रहा है तो इससे असंगठित क्षेत्र में उद्योगों के पनपने को बढ़ावा मिलता है और शहरों में झुग्गी-बस्तियों का विस्तार होता है। ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों को विशेष रियायत दी जाए। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिये विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक, छपरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

नेपाल ने स्वर्ण आयात शुल्क बढ़ाया

पड़ोसी देश के इस कदम से भारत को भी मिलेगी अवैध सोने पर लगाम लगाने में मदद

राजेश भयानी
मुंबई, 26 नवंबर

भारत के साथ खुली सीमा साझा करने वाले नेपाल की सरकार द्वारा सोने और चांदी के आयात शुल्क में इजाफा करने के फैसले से भारत और नेपाल दोनों ही देशों को मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह नेपाल सरकार ने सोने और चांदी के आयात शुल्क में तीव्र वृद्धि की है।

नेपाल सरकार अब 50 ग्राम तक वजन वाली सोने की छड़ों के आयात पर प्रति 10 ग्राम 7,500 रुपये (नेपाली रुपये) का सीमा शुल्क लगाएगी जो पहले प्रति 10 ग्राम 6,200 रुपये था। इसी प्रकार 50 ग्राम से 100 ग्राम तक वजन वाली छड़ों पर प्रति 10 ग्राम 8,500 रुपये (पहले यह प्रति 10 ग्राम 7,200 रुपये था) और 100 ग्राम से अधिक वजन वाली छड़ों पर प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपये का सीमा शुल्क वसूला जाएगा जो पहले प्रति 10 ग्राम 8,500 रुपये था।

नेपाल में जौहरियों के शीर्ष संगठन के जरिये स्वर्ण आयात की व्यवस्था है। नेपाल में सोने का आयात कोटे के आधार पर होता है और प्रतिदिन 20 किलोग्राम स्वर्ण आयात की ही अनुमति रही है। नेपाल के केंद्रीय बैंक – नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिदिन केवल 20 किलोग्राम स्वर्ण आयात की ही अनुमति देता है। मांग में इजाफे वाली अवधि के दौरान इस कोटे में पांच किलोग्राम तक की और वृद्धि की जा सकती है। हालांकि स्थानीय मांग पूरी करने के लिए जौहरियों को हर रोज 40-50 किलोग्राम सोने की जरूरत रहती है। आधिकारिक रूप से प्रतिदिन 20 किलोग्राम के इस आयात में से कुछ हिस्सा अवैध तरीके से भारत में आ रहा था जिससे नेपाल के जौहरियों की आपूर्ति में और ज्यादा कमी हो रही

मेटल फोकस के वरिष्ठ सलाहकार चिराग शेठ ने कहा कि नेपाल सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ते गैरकानूनी प्रवाह को रोकना प्रतीत होता है क्योंकि जुलाई के बाद से शुल्क का अंतर बढ़ गया है।

नेपाल की मुद्रा भारतीय रुपये से आंकी जाती है और सोने का आयात बढ़ने (कुछ भाग भारत भेजे जाने से) के कारण नेपाल के अधिकारी देश के चालू खाते पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंतित थे। नेपाल में पहले ही चीन से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से सोने का आयात किया जा रहा था और इसका कुछ हिस्सा भारत में भी जा रहा था। इस तरह आधिकारिक तौर पर नेपाल के जौहरियों को सोने की जरूरत का आधा हिस्सा ही मिल पा रहा है। यह कदम भारतीय सराफा व्यापार के लिए भी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत में सोने की तस्करी में तेज इजाफा देखा गया है, खासकर जुलाई में आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किए जाने के बाद से।

पिछले साल भारत में 100 टन से ज्यादा सोने की तस्करी किए जाने का अनुमान है। सोने के दामों में तेज उछाल के कारण जुलाई के बाद से चार महीने के दौरान स्वर्ण आयात तकरीबन 120 टन रहा है। इसमें से बामुश्किल 30-35 प्रतिशत ही घरेलू उपभोग के लिए रहा।

नेपाल सरकार ने चांदी के आयात शुल्क में भी इजाफा किया है। चांदी पर सीमा शुल्क प्रति 10 ग्राम 56 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। जुलाई में भारत सरकार द्वारा कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किए जाने के बाद इन दोनों देशों के बीच शुल्क का अंतर बढ़ गया था। परिवर्तित शुल्क दरों और नेपाल में सोने के प्रचलित दामों के आधार पर नेपाल में मौजूदा शुल्क प्रभावी तौर पर 10.5 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत के बीच है। हालांकि शुल्क में इजाफे के बाद भारत की तरह नेपाल में भी सोने की मांग में गिरावट आने की संभावना है।

नेपाल सरकार ने शुल्क दर संशोधित किया

- नेपाल सरकार अब 50 ग्राम तक वजन वाली सोने की छड़ों के आयात पर प्रति 10 ग्राम 7,500 रुपये (नेपाली रुपये) का सीमा शुल्क लगाएगी जो पहले प्रति 10 ग्राम 6,200 रुपये था
- 50 ग्राम से 100 ग्राम तक वजन वाली छड़ों पर प्रति 10 ग्राम 8,500 रुपये लगाएगी जो पहले यह प्रति 10 ग्राम 7,200 रुपये था
- 100 ग्राम से अधिक वजन वाली छड़ों पर प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपये सीमा शुल्क वसूला जाएगा जो पहले प्रति 10 ग्राम 8,500 रुपये था

अलौह धातु कंपनियों की बिक्री में आई 5 फीसदी तक की गिरावट

जयजित दास
भुवनेश्वर, 26 नवंबर

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अलौह धातु कंपनियों की बिक्री में 4.7 फीसदी तक की कमी आई है। सभी धातुओं की कीमतों में नरमी के कारण ऐसा हुआ है। अलौह धातु कंपनियों में एल्युमीनियम कंपनियों की बिक्री में 21 फीसदी की गिरावट हुई है। केयर रेटिंग्स के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में एल्युमीनियम की औसत कीमत पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 14 फीसदी घटी है। एल्युमीनियम के अलावा जस्ते और तांबे जैसी दूसरी मूल धातुओं की औसत कीमतों में क्रमश: 7.5 फीसदी और 5 फीसदी की कमी आई है। इससे कंपनियों के राजस्व पर नकारात्मक असर हो रहा है। धातु क्षेत्र के लिए शुद्ध बिक्री में आई कमी मोटे तौर पर सभी खंडों के नतीजों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में समग्र धातु क्षेत्र की बिक्री में 13 फीसदी की गिरावट आई जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 18.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी।

कीमत में कमी के साथ ही एल्युमीनियम उत्पादकों को सुस्त पड़ती मांग से भी जूझना पड़ रहा है।

इस साल सितंबर के अंत में घरेलू मांग में मामूली 0.1 फीसदी की वृद्धि हुई। एल्युमीनियम की खपत में दिख रही मजबूत मांग घरेलू उत्पादकों के लिए सकारात्मक संकेत है जिससे उन्हें लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर नरम चल रही कीमतों से मुकाबला करने में मदद मिल रही है।

एलएमई पर एल्युमीनियम की कीमत सितंबर 2019 के अंत में 1,762 डॉलर प्रति टन रही जो एक वर्ष पहले की समान अवधि के मुकाबले 14 फीसदी कम है। भारतीय एल्युमीनियम की मांग वैश्विक मांग के अनुरूप नजर आ रही है जहां कैलेंडर वर्ष 2019 में वृद्धि में 0.4 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम है।

एल्युमीनियम कंपनियों की बिक्री में 21 फीसदी की गिरावट आई

कैलेंडर वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय एल्युमीनियम बाजारों में 12 लाख टन की कमी रहने की संभावना है जो कैलेंडर वर्ष 2018 में दर्ज किए गए 13 लाख टन से 1 लाख टन कम है।

उद्योग से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'घरेलू एल्युमीनियम निर्माताओं के लिए घटती मांग चिंता का विषय है। परिवहन और निर्माण क्षेत्र में कमजोर मांग के कारण फ्लैट रॉल्ड उत्पादों (एफआरपी) में भी नकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। उत्पादन क्षेत्र में सुस्ती, कमजोर उपभोक्ता मांग और नरम पड़ी निवेश गतिविधियों के कारण एल्युमिनियम खपत धीमी पड़ गई है।'

इसी तरह से जस्ते की कीमतों में सुस्ती ने वेदांत समूह की नियंत्रण वाली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) जैसे महत्त्वपूर्ण उत्पादकों पर असर डाला है। कमजोर मांग और सुस्त कीमतों के कारण दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा 8 फीसदी घटकर 2,120 करोड़ रुपये रहा। दूसरी तिमाही के दौरान परिचालनों से एचजेडएल का राजस्व सालाना आधार पर छह फीसदी घटकर 4,511 करोड़ रुपये रहा। इसकी वजह बेंचमार्क एलएमई पर कीमतों में औसतन छह फीसदी की गिरावट और सीसे और चांदी की मात्रा का कम रहना भी है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Nov 26	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,753.0	0.4	1,860.1	-5.0
Copper	5,872.5	3.5	6,153.8	0.0
Nickel	14,570.0	-7.5	15,174.8	-4.6
Lead	1,945.0	-6.6	2,125.9	4.2
Tin	16,350.0	1.9	17,202.8	2.4
Zinc	2,335.0	3.3	2,643.4	4.0
Gold ($/ounce)	1,456.9*	-4.6	1,644.4	-1.3
Silver ($/ounce)	16.9*	-4.2	19.2	-1.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.4*	8.7	64.2	7.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.5*	10.8	2.5	14.7
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	184.1	12.9	299.3	3.5
Maize	182.3*	-0.5	302.0	-1.3
Sugar	342.4*	10.3	485.6	1.3
Palm oil	652.5	18.1	1,030.1	17.8
Rubber	1,551.8*	6.4	1,832.2	-5.4
Coffee Robusta	1,407.0*	10.0	1,881.1	-13.4
Cotton	1,426.6	12.2	1,568.9	-8.3

* As on Nov 26, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.5& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	53.5	13513
Oil and Oilseeds	382.8	80316
Spices	0.6	14
Metal(Nov 25)		
Metal- non ferrous	4812.1	62712
Metal- precious	9078.0	563
Oil and gas(Nov 25)		
Gas	3679.3	38853
Oil	15940.7	2145

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	124.2	109605
Grains	225.2	106320
Oil and Oilseeds	592.9	457620
Others	168.7	69335
Pulses	98.5	65080
Spices	74.7	31552

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Mentha Oil (Nov 29)	1266.1	1.3
Kapas (Apr 30)	1078.5	0.6
Cotton (Nov 29)	19070.0	0.1
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Nov 25)	181.3	-4.8
Lead (Nov 29)	151.1	-2.0
Gold Petal (Nov 29)	3818.0	-2.0
Nickel (Nov 29)	1069.1	-1.5
Gold Guinea (Nov 29)	30291.0	-1.4
Cardamom (Dec 13)	2843.9	-1.2
Lead Mini (Nov 29)	151.9	-1.1
Zinc Mini (Nov 29)	186.2	-1.0
Zinc (Nov 29)	186.9	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	16255.0	1.2
Moong-Mertacity (Dec 20)	6650.0	1.1
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1077.5	0.4
Coriander-Kota (Dec 20)	6833.0	0.1
Losers (* % Change)		
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7473.0	-1.7
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4184.0	-1.3
Guar Seed 10 (Dec 20)	4117.5	-0.8
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5600.0	-0.8
Chana-Bikaner (Dec 20)	4444.0	-0.8
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2070.5	-0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	804.9	-0.5
Soyabean Indore (Dec 20)	4042.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	4.2
Cotton-Rajkot (Nov 29)	19070.0	2.2
Gold Petal-Mumbai (Nov 29)	3818.0	0.6
Silver Micro-Ahemd (Nov 29)	44245.0	0.1
Silver Ahm (Dec 05)	44237.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Nov 29)	1266.1	-9.3
Alumini-Mumbai (Nov 29)	129.0	-7.0
Aluminium Mum (Nov 29)	129.2	-6.8
Copper Mum (Nov 29)	428.0	-5.0
Lead Mum (Nov 29)	151.1	-2.8
Lead Min Mumbai (Nov 29)	151.9	-2.3
Nickel Mumbai (Nov 29)	1069.1	-1.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Maize-Sangli (Dec 20)	1901.0	2.8
Moong-Merta City (Dec 20)	6650.0	1.7
Crude Palm Oil Kandl (Nov 29)	681.7	1.0
Barley Jaipur (Dec 20)	2132.5	0.5
Soy Bean Indore (Dec 20)	4042.0	0.4
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18550.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5600.0	-5.9
Coriander-Kota (Dec 20)	6833.0	-4.2
Jeera Unjha (Dec 20)	16255.0	-1.8
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7473.0	-1.7
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3200.0	-1.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	95.....(95)
Aluminium ingots /kg	133.....(133)
Brass sheet cutting /kg	312.....(312)
Brass utensil scraps/kg	291.....(295)
Copper heavy scrap /kg	407.....(406)
Copper utensil scraps/kg	380.....(380)
Copper wire bar /kg	440.....(440)
Lead ingots /kg	152.....(152)
Nickel Cathodes /kg	1085.....(1100)
Tin slabs /kg	1230.....(1225)
Zinc slabs /kg	189.....(191)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10686.....(10686)
DCH - 32 /Qtl	11445.....(11473)
Jaydhar /Qtl	10208.....(10292)
Shankar- 6 /Qtl	11304.....(11417)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	900.....(905)
Castor Comm /10kg	890.....(895)
Ricebran oil/10kg	760.....(760)
Groundnut oil /10kg	1020.....(1020)
Linseed oil /10kg	845.....(845)
Karanji /10kg	790.....(800)
Palm oil /10kg	740.....(745)
Sunflower exp ref /10kg	830.....(830)
Sunflower oil exp /10kg	790.....(795)
Soyabean ref / 10kg	785.....(790)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3562 .....(3382-3570)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	58.04.....(58.01)
Brent Crude (UK)	63.2 .....(63.05)
Brent Crude (WTI)	57.94.....(57.94)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.47 .....(2.53)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	249.59 .....(250.86)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37802.....(37871)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	37954.....(38023)
Silver.999/ kg	44250.....(44250)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18477.20	18519.05
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.25	138.60
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1900.00	1900.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2123.90	2120.95
Brass-Jamnagar (M)	1 K	298.00	297.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2983.00	3000.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4296.90	4285.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4300.00	4280.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4376.30	4357.35
Chana Delhi (N)	1 Q	4520.45	4500.00
Chana-Akola (N)	X	4471.90	4462.50
Coriander-Gondal (N)	X	6900.00	6775.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7125.00	7150.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7148.60	7135.55
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2146.15	2116.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2062.15	2060.45
Cotton-Kadi (N)	1 B	18429.40	18477.20
CPO-Kandla (M)	10 K	670.80	666.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	681.20	674.80
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	873.50	873.25
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1540.75	1539.00
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3475.65	3470.10
Gold Ahm (M)	10 G	37862.00	37799.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30411.00	30361.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3804.00	3797.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7785.65	7600.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4141.65	4077.15
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4167.00	4075.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1010.05	1010.20
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	92.05	92.50
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	17100.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16484.10	16557.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1009.85	1008.90
Kapas-Rajkot (N)	X	994.75	996.20
Lead Mum (M)	1 K	156.00	155.40
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1866.25	1866.25
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2150.00	2148.35
Maize-Erode (N)	X	1881.00	1897.20
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2080.00	2100.00
Maize-Sangli (N)	X	1843.35	1850.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	6556.25	6540.65
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4501.40	4475.65
Nickel Mumbai (M)	1 K	1098.00	1086.30
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3187.50	3250.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3202.00	3253.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	346.00	350.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34033.35	34623.10
Rape mustards-Patan (I)	20 K	796.00	787.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2100.00	2092.50
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	743.75	736.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	805.00	800.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	798.80	802.90
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	806.50	803.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13075.00	13083.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44194.00	44181.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4048.00	4024.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3987.50	4014.75
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3964.25	3984.75
Soy Bean-Akola (N)	X	4000.00	4000.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33300.00	33331.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	805.40	798.20
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27800.00	27810.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28700.00	28700.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25950.00	25930.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3395.00	3345.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3419.00	3428.55
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3296.25	3296.25
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3519.05	3523.80
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3357.50	3350.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3116.90	3126.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5948.70	5948.70
Wheat Delhi (N)	1 Q	2270.85	2272.50
Wheat Kota (N)	1 Q	2131.80	2132.80
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2080.00	2075.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2240.00	2240.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4615.20	4600.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	190.00	189.00

* as on Nov 25, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

हमारे कॉटन फाइबर प्रोडक्ट्स का अब किया गया है विस्तार!
MCX METAL & ENERGY Trade with Trust
कपास कॉन्ट्रैक्ट अब व्यापार के लिए उपलब्ध
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें
www.mcxindia.com

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Nov 29	19140, 19190, 19060, 19070	719	133	1539
Dec 31	19170, 19390, 19170, 19310	3023	511	9043
Jan 31	19350, 19510, 19350, 19470	706	100	2211
Apr 30	19150, 19180, 19150, 19170	09	2	09
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2085, 2106, 2064.5, 2070.5	23790	1637	46800
Jan 20	2084, 2113.5, 2063, 2070.5	20510	1448	35250
Feb 20	2086.5, 2120, 2075, 2078.5	1940	146	21270
Mar 20	2111, 2135, 2095, 2119.5	460	44	2370
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1074, 1084.5, 1074, 1078.5	536	103	652
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1075, 1083.5, 1074, 1077.5	1236	642	3915
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4172, 4172, 4109, 4117.5	37950	3105	74780
Jan 20	4191, 4206.5, 4146, 4156	15990	1347	28590
Feb 20	4218, 4224.5, 4190, 4207.5	310	31	570
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4240, 4272, 4158, 4184	8585	700	46190
Jan 20	4270, 4302, 4200, 4216	3425	405	16295
Feb 20	4200, 4210, 4160, 4186	235	39	3310
Mar 20	4160, 4174, 4110, 4154	240	36	2405
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Nov 29	661.5, 669.1, 655.9, 667.3	16450	964	20150
Dec 31	668, 670.9, 656.5, 669.1	34960	2083	50430
Jan 31	663.1, 670, 657.9, 668.8	1750	134	9370
Mentha Oil MCX(1 K)				
Nov 29	1253, 1270.2, 1252.7, 1266.1	38.52	45	88.92
Dec 31	1265, 1278, 1263.5, 1275.1	198.36	450	277.2
Jan 31	1282.2, 1282.2, 1282.2, 1282.2	0.36	1	0.36
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4320, 4340, 4308, 4334	6880	558	31030
Dec 20	4330, 4346, 4318, 4341	2340	199	3730
Apr 20	4235, 4255, 4235, 4255	40	4	720
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	802, 807.2, 797.5, 804.9	15220	1077	42890
Jan 20	804.2, 810.45, 799.55, 808.5	9940	606	36800
Feb 20	805.65, 809.2, 803.1, 809.2	80	8	1200
Mar 20	805, 809, 805, 809	20	2	10
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4033, 4062, 4015, 4042	34550	2743	80570
Jan 20	4051, 4078, 4029, 4061	23140	1879	115480
Feb 20	4066, 4099, 4049, 4082	11890	1013	63280
Mar 20	4090, 4130, 4089, 4121	3810	348	13590
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7606, 7606, 7450, 7473	13525	1773	42235
Jan 20	7709, 7712, 7560, 7584	8615	1057	26900
Feb 20	7772, 7772, 7692, 7692	70	5	150
Mar 20	-, 8171, -, 8171	50	1	50
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4481, 4489, 4434, 4444	15180	1012	39470
Jan 20	4485, 4489, 4435, 4443	6500	393	24570
Mar 20	4455, 4465, 4400, 4434	380	34	840
Apr 20	4412, 4412, 4405, 4405	30	2	50
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	6650, 6650, 6650, 6650	25	1	100
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2864.4, 2900, 2820, 2843.9	1.1	11	5
Jan 15	2834, 2850, 2774, 2817.4	0.9	9	7.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6800, 6918, 6730, 6833	2460	231	9840
Jan 20	6650, 6800, 6610, 6708	780	67	3140
Apr 20	7050, 7125, 7020, 7077	160	16	2010
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16075, 16340, 16030, 16255	1989	496	3057
Jan 20	15880, 16070, 15860, 16010	396	130	792
Mar 20	15600, 15630, 15600, 15630	33	11	213
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5678, 5678, 5570, 5600	1350	246	10050
Mar 20	6006, 6050, 5940, 5974	550	104	1325
Apr 20	6008, 6032, 5962, 5996	260	49	1120
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Nov 29	129.45, 130.8, 128.9, 130.75	475	85	935
Dec 31	131, 132, 130.3, 131.85	5435	756	8215
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Nov 29	128.75, 131.1, 128.75, 130.65	215	173	1299
Dec 31	131.3, 132, 130, 131.8	1938	1619	3415
Jan 31	133, 133.45, 133, 133.4	43	36	49
Copper MCX(1 K)				
Nov 29	427.7, 428, 426.7, 426.9	602.5	213	1070
Dec 31	433.7, 433.7, 432.05, 432.8	10955	3608	15152.5
Jan 31	438, 438.25, 437.5, 437.9	62.5	25	512.5
Lead MCX(1 K)				
Nov 29	152.35, 155.85, 152.3, 155.2	380	66	215
Dec 31	152.85, 153.2, 152.65, 153.05	7235	1142	8240
Lead Mini MCX(1 K)				
Nov 29	153, 156, 152, 155.65	75	54	35
Dec 31	152.8, 153.25, 152.45, 153.05	2709	2102	2882
Jan 31	154, 154, 152.95, 153.15	21	18	22
Nickel MCX(1 K)				
Nov 29	1072, 1077.3, 1055.6, 1056.5	394.5	657	65.25
Dec 31	1064.9, 1068.7, 1058.3, 1059.5	6849	4085	2410.5
Jan 31	1060.8, 1061.9, 1056.5, 1060.2	30	19	33
Zinc MCX(1 K)				
Nov 29	187.3, 190.3, 186.8, 187.3	1590	203	795
Dec 31	186, 186.1, 185, 185.3	15875	2649	17895
Zinc Mini MCX(1 K)				
Nov 29	187, 187, 186, 186.55	91	89	143
Dec 31	186.3, 186.3, 185.1, 185.35	4989	3772	5371
Jan 31	186.2,

नई दिल्ली | 27 नवंबर 2019 बुधवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

चुनावी बॉन्ड: क्रम से पहचान होगी जाहिर

सोमेश झा
नई दिल्ली, 26 नवंबर

वित्त मंत्रालय ने चुनावी बॉन्ड पर क्रम संख्या डालने को लेकर अनिच्छा जताई थी। उसका पक्ष था कि इससे दानदाताओं की पहचान उजागर होने की संभावना है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर चिंता जताने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गया था। कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) और अंजलि भारद्वाज द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुटाए गए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद एसबीआई ने वित्त मंत्रालय के समक्ष कुछ चिंताएं जताई थीं।

यह कवायद चुनावी बॉन्ड के लिए केंद्र सरकार की ओर से रूपरेखा जारी किए जाने के बाद हुई थी। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को राजनीतिक दलों को गुप्त चंदा मुहैया कराने के लिए वित्तीय व्यवस्था के तौर पर चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था शुरू की थी।

एसबीआई ने 19 जनवरी, 2018 को लिखे पत्र में कहा कि चूंकि बॉन्ड पर खरीदार का नाम नहीं होगा ऐसे में उन्हें इस पर एक क्रम संख्या की जरूरत होगी अन्यथा उनके पास आंतरिक नियंत्रण और मिलान करने के लिए कोई लेखा जांच की गुंजाइश नहीं होगी। ऐसी स्थिति में शाखा के स्तर पर चुनावी बॉन्ड की वास्तविकता की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाएगा।

बिनय सिन्हा

इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण तैयार किया जिसमें कहा गया कि क्रम संख्या डालने पर दानदाता और राजनीतिक दल के बीच एक संपर्क स्थापित होगा जिससे राजनीतिक दल ऐसे बॉन्ड का उपयोग करने को लेकर हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए एसबीआई चुनावी बॉन्डों की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए होलोग्राम आदि अन्य सुरक्षा उपायों के बारे में सोच सकता है।

इसमें आगे कहा गया था कि यदि ऐसा कर पाना संभव नहीं हो तो एक क्यूआर कोड या अदृश्य स्याही से कोई संख्या देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, एसबीआई और सरकारी कंपनी भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के बीच बैठक होने के बाद वित्त मंत्रालय अपने रुख में नरमी लाने को तैयार हो गया था। 6 फरवरी को एसपीएमसीआईएल को चुनावी बॉन्ड के मुद्रण के लिए अधिकृत किया गया था। 9 फरवरी, 2018 को वित्त मंत्रालय ने एसबीआई को भेजी अपनी प्रतिक्रिया में अपने रुख से पलटते हुए कहा कि एसबीआई की ओर से उठाए गए मुद्दे वैध हैं और बिना किसी विशिष्ट क्रमांक के बॉन्ड जारी करने से बैंक के लिए बहुत सी परिचालन संबंधी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी इसके साथ ही बैंक पर बहुत अधिक जोखिम भी आ जाएगा। उसने बैंक को बॉन्ड पर क्रमांक डालने की मंजूरी दे दी। इसको लेकर किसी तरह के विवाद को दूर रखने के लिए उसने बैंक से सूचना को उच्च स्तरीय तौर गुप्त रखने की सलाह दी थी। चुनावी बॉन्ड पहली बार मार्च 2018 में जारी किया गया था। अप्रैल में न्यूज पोर्टल द क्विंट ने खबर दी थी कि इन बॉन्डों पर गुप्त अक्षरांकीय कोड मुद्रित है जिसे पराबैंगनी प्रकाश में देखा जा सकता है। ऐसा एसबीआई और एसपीएमसीआई के बीच फरवरी में हुई बैठक में हुए समझौते के तहत किया गया था जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने क्रम संख्या पर अपने रुख में बदलाव किया था।

चुनावी बॉन्डों पर एक गुप्त विशिष्ट संख्या होने की मीडिया रिपोर्टों के बाद वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने अप्रैल 2018 में अहस्ताक्षित एक हस्तलिखित नोट तैयार किया जो आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें कहा गया था कि हमने विस्तृत फीचर डालने को नहीं कहा था। हमने कोई विशिष्ट संख्या डालने से इनकार कर दिया था जिसके लिए एसबीआई ने हमसे मांग की थी।

दिलचस्प है कि 2017 में जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ चुनावी बॉन्ड जारी करने की इजाजत देने के लिए बातचीत कर रही थी तब रिजर्व बैंक ने भी इन बॉन्डों के लिए एक विशिष्ट पहचान का प्रस्ताव दिया था। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ऊर्जित पटेल ने 14 सितंबर, 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे पत्र में प्रस्तावित चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी विभिन्न आपत्तियों से अवगत कराया था। पत्र में उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक कुछ शर्तों के साथ ही चुनावी बॉन्ड के मामले में आगे बढ़ सकता है जिसमें एक विशिष्ट पहचान और एक अतिरिक्त सुरक्षा फीचर आधारित आईडी शामिल है।

ससम्मान कर्ज समस्या का समाधान

जिस बाजार में प्रवर्तक भगोड़े बन जाते हैं या कंपनी पर कुंडली मारे बैठे रहते हैं, उसमें सुभाष चंद्रा ने ज़ी से निकलकर सम्मान के साथ कर्ज समस्या के समाधान का पैमाना तय किया है

वनिता कोहली-खांडेकर

ज़ी के चेयरमैन पद से सुभाष चंद्रा के इस्तीफे को 'दुखद' या 'एक युग का अवसान' करार देना गलत है। जो गुण 69 वर्षीय चंद्रा को एक अच्छा उद्यमी बनाते हैं, वह उनकी लगन और जोखिम लेने की क्षमता हैं। हालांकि इन्हीं गुणों से मौजूदा हालात भी पैदा हुए हैं। जब ये गुण कारगर रहे तो एक बंद दाल मिल से 30,000 करोड़ रुपये का एस्सेल समूह खड़ा हो गया। जब इन गुणों ने काम नहीं किया तो उनका समूह कर्ज संकट में फंस गया और प्रवर्तक परिवार को ज़ी एंटरटेनमेंट में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखनी पड़ी। कर्जदाताओं ने अपना पैसा मांगा और चंद्रा का ज़ी पर नियंत्रण छिन गया। लेकिन यह उतनी गंभीर बात नहीं है, जितनी लोग मान रहे हैं। इस बात पर गौर करें कि उन्होंने कंपनी से निकलकर क्या हासिल किया है।

पहला, इससे ज़ी मुक्त हो गया है। भारतीय मीडिया कंपनियों के लिए अपने संस्थापक परिवार की छत्र छाया से बाहर निकलना बहुत दुर्लभ है। हालांकि यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। चंद्रा ने परिचालन शुरू करने के दूसरे साल 1993 में कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। इस तरह उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की, जो अब तक करीब 26 वर्षों से बाजार की निगरानी झेल चुकी है। यह उन मामलों में संस्थागत है, जिनमें मालिक की अगुआई वाली ज्यादातर कंपनियां नहीं हैं। यह इसे दूसरों से बेहतर क्यों बनाता है, जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है।

पिछले सप्ताह परिवार की हिस्सेदारी घटकर पांच फीसदी पर आ

चित्रांकनः अजय मोहंती

गई, जो इस साल की शुरुआत में 20 फीसदी थी। कंपनी के मौजूदा मालिकों- सभी वित्तीय या संस्थागत निवेशकों को किसी समय निकासी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि ज़ी को बेचा जाएगा, संभवतया किसी रणनीतिक निवेशक को। कंपनी के शेयरों के गिरवी रखे होने की मुख्य वजह यह थी कि यह एस्सेल के पोर्टफोलियो में सबसे अहम कंपनी है। ज़ी करीब 8,000 करोड़ रुपये की कंपनी है। यह विश्व के सबसे आकर्षक मीडिया बाजारों में से एक (भारत) में नकदी उगलने वाली बाजार की अगुआ कंपनी है।

प्रवर्तकों के हाथ से नियंत्रण छिनने की खबरों के बाद ज़ी के शेयर में 12 फीसदी बढ़त दर्ज की गई। इसकी वजह यह है कि बाजार यह जानता है कि रणनीतिक निवेशक कोई भी हो, ज़ी अब अपने प्रवर्तकों के कर्ज की जंजीरों से मुक्त हो गई है। अब निवेशक जो पूंजी लगाएगा, वह कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाएगी। विशेष रूप से उस बाजार में, जिसमें नई इबारत लिखी जा रही है। पिछले साल डिज्नी ने स्टार का अधिग्रहण किया था। इस तरह वह करीब 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी के साथ भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई। गूगल, नेटफ्लिक्स और जियो नई प्रतिस्पर्धी कंपनियों के रूप में उभर रही हैं। सोनी के वायकॉम 18 को खरीदने की खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो यह 10,000 करोड़ रुपये की कंपनी बन जाएगी, जो ज़ी से बड़ी होगी। ज़ी को अपनी प्रतिस्पर्धा को नई धार देने की जरूरत है। चंद्रा के कंपनी से बाहर निकलने से ज़ी नई उड़ान भरने के लिए मुक्त हो गई है। उसके पास बड़ी वैश्विक कंपनी बनने का मौका आया है।

दूसरा, उनकी निकासी ने यह बेंचमार्क तय किया है कि कैसे उद्यमियों और कंपनियों को अपने कर्ज संकट से निपटना चाहिए। चंद्रा शुरुआत से ही ईमानदार रहे हैं। अन्य बहुत से भारतीय कारोबारियों से इतर वह भागे नहीं, कोई हथकंडा अपनाकर कंपनी पर कुंडली मारने या मौजूदा सरकार के साथ अपनी नजदीकी का इस्तेमाल करके कर्ज समस्या से निपटने की कोशिश नहीं की। जब जनवरी में उनका शेयर गिरा तो उन्होंने अपने बैंकरों और कर्जदारों से माफी मांगी और कहा कि उन्होने कुछ गलत फैसले लिए हैं। हालांकि प्रसारण बाजार में उनके कुछ छल-कपट से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन कंपनी पर नियंत्रण छोड़ने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इससे लोगों का बड़ी कंपनियों में भरोसा बहाल होता है।

चावल से सड़क तक का सफर

1960 के दशक में हिसार से दिल्ली तक के सफर में 18 वर्षीय सुभाष चंद्रा की अमन सिंह से दोस्ती हुई, जो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में सहायक प्रबंधक थे। चंद्रा ने तभी चावल-दाल पॉलिश के पारिवारिक कारोबार को उबारा था। उस समय एफसीआई देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा खरीदार था। भारतीय सेना खाद्य मंत्रालय से अनाज खरीदती थी। इसके लिए मंत्रालय निविदा आमंत्रित करता था। चंद्रा ने सिंह से पूछा कि सेना एफसीआई से सीधे खरीद क्यों नहीं करती है? सिंह ने कहा कि एफसीआई कच्चा खाद्यान्न खरीदता है, इसलिए इसका प्रसंस्करण जरूरी है। चंद्रा ने एफसीआई के खाद्यान्न को प्रसंस्कृत करने की पेशकश की ताकि इसे सीधे सेना को आपूर्ति किया जा सके। सिंह को चंद्रा की क्षमता पर संदेह था, लेकिन उन्हें यह विचार पसंद आया। सिंह ने प्रस्ताव मंत्रालय के सामने रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। चंद्रा इस कारोबार में उतर गए।

यह उनके जीवन का अहम मोड़ था। चंद्रा ने एक बार बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया था, 'इससे मुझे आत्मविश्वास और विचार मिला कि जहां चाह वहां राह।'

इसी आत्मविश्वास के चलते उन्होंने एक के बाद एक नए कारोबारों जैसे पैकेजिंग, प्रकाशन, लेजर पार्क, प्रसारण, केबल, डीटीएच, इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी आदि में दांव लगाया।

उनके लिए बड़ा मौका दिसंबर 1991 में संभवतया हॉन्ग कॉन्ग में आया। चंद्रा और एडमैन अशोक कुरियन (ज़ी के सह-संस्थापक) नए शुरू हुए स्टार टीवी के अध्यक्ष डेविड मैनियन के साथ एशियासैट1 का एक ट्रांसपोंडर लीज पर लेने के लिए बातचीत कर रहे थे। उपग्रह पर एक समूह का स्वामित्व था, जिनमें हॉन्ग कॉन्ग के अरबपति ली का शिंग भी शामिल थे। उनके बेटे रिचर्ड ली ने इस पर स्टार टीवी शुरू किया था। उस समय यह चीन और भारत में प्रसारण करने वाला एकमात्र उपग्रह था। चंद्रा जानते थे कि भारतीय बाजार में जल्द ही प्रसारकों की बाढ़ आने वाली है। वह उस उपग्रह के जरिये अन्य से पहले एक हिंदी चैनल शुरू करना चाहते थे। मैनियन ने उन्हें 50:50 के संयुक्त उद्यम के लिए बातचीत करने को आमंत्रित किया। ट्रांसपोंडर की लीज की लागत 12 लाख डॉलर प्रति वर्ष यानी तब तीन करोड़ रुपये से अधिक थी। हालांकि ली ने सालाना करीब 13 करोड़ रुपये से कम में ट्रांसपोंडर लीज पर देने से इनकार कर दिया। यह कीमत समझौते की रकम से चार गुना थी। इससे क्रोधित चंद्रा जोखिम की चिंता किए बिना 50 लाख डॉलर चुकाने को तैयार हो गए। वह उपग्रह के सहारे टीवी चैनल शुरू करना चाहते थे। ली के मई 1992 में सहमत होने से पहले पांच महीने और लग गए। उस साल अक्टूबर में चंद्रा ने ज़ी टीवी शुरू कर दिया।

सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं दायर करेगा पुनर्विचार याचिका

बीएस संवाददाता

अयोध्या मामले के प्रमुख पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। इस तरह अयोध्या विवाद पर मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था माने जाने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग-थलग पड़ता दिख रहा है। बोर्ड ने जहां अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है, वहीं मामले के अहम पक्षकार इससे अलग हो गए हैं। मंगलवार को बाबरी मस्जिद मामले के अहम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की लखनऊ में हुई बैठक में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का फैसला लिया गया है।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला बदल लिया है। पहले बोर्ड ने कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। लेकिन अब बोर्ड ने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रज्जाक खान ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में बहुमत से यह फैसला लिया गया है कि अयोध्या विवाद में पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल की जाएगी।

फैसले में अयोध्या में मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और पांच एकड़ जमीन दिए जाने को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि बोर्ड की बैठक में ज्यादातर लोगों की राय जमीन न लेने की

रही पर अंत में इसके लिए फिर से एक बैठक बुलाने का फैसला किया गया। बोर्ड के अधिकतर सदस्यों का कहना था कि पहले सरकार की ओर से पांच एकड़ जमीन का प्रस्ताव तो आए फिर इस पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा देश भर की जानी-मानी 100 मुस्लिम हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के बोर्ड के कदम का विरोध किया था। इनमें शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। इनका कहना था कि इस मुद्दे को जिंदा रखने से मुस्लिम समुदाय को फायदा नहीं होगा। अयोध्या विवाद मामले में मुसलिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा था कि उन्हें उच्चतम न्यायालय का फैसला मंजूर है और देशभर के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी ने लंबे समय तक इस मामले में मुकदमा लड़ा था।

गौरतलब है कि 9 नवंबर को दिए अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल रामलला को और मसजिद के लिए मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।